सत्यमेव जयते

MINISTRY OF COAL

वर्ष 2014 से
कोयला मंत्रालय की उपलब्धियां

सत्यमेव जयते

कोयला मंत्रालय

कोयला मंत्रालय

वर्ष 2014 से कोयला मंत्रालय के सुधार एवं उपलब्धियां

श्री नरेंद्र मोदी
भारत के प्रधान मंत्री

भारत की प्रगति के लिए, आत्मानिर्भर भारत के लिए, ऊर्जा स्वतंत्रता आवश्यक है, भारत को यह संकल्प लेना होगा कि जिस वर्ष हम स्वतंत्रता के 100वें वर्ष का जश्न मनाएंगे, वह ऊर्जा स्वतंत्र होगा।

– श्री प्रल्हाद जोशी

कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री

कोयला मंत्रालय का लक्ष्य तापीय कोयले के आयात को कम करना और देश को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है।

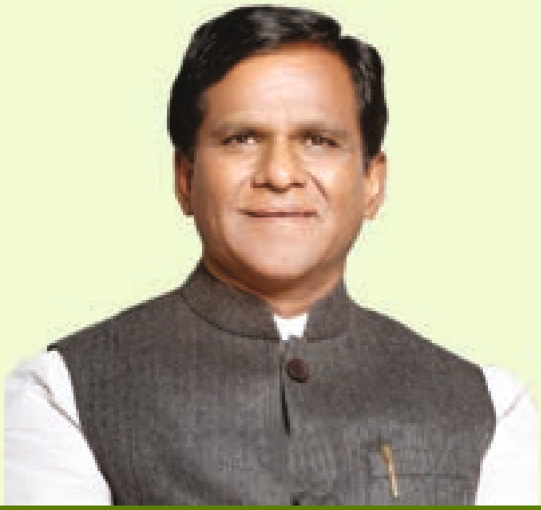

श्री रावसाहेब पाटिल दानवे
कोयला, खान और रेल राज्य मंत्री

सरकार का लक्ष्य वित्त वर्ष 23-24 तक घरेलू कोयला उत्पादन को 1.2 अरब मीट्रिक टन तक बढ़ाना है

अनुक्रमणिका

क्रमांक	अध्याय		पृष्ठ सं.
1.	**परिचय**		0 - 1
2.	**कोयला मंत्रालय में सुधार**		2 - 15
	2.2	2015	2 - 5
	2.3	2016	5 - 6
	2.4	2017	6 - 7
	2.5	2018	7 - 9
	2.6	2019	9 - 10
	2.7	2020	10 - 12
	2.8	2021 के बाद से	13 - 15
3.	**कोयला मंत्रालय में उपलब्धियां**		16 - 35
	3.1	वाणिज्यिक खनन	16 - 17
	3.2	कोयला आयात प्रतिस्थापन	17 - 18
	3.3	पावर सेक्टर लिंकेज पॉलिसी-शक्ति	19 - 19
	3.4	कोयला लिंकेज का युक्तिकरण	20
	3.5	थर्ड पार्टी सैंपलिंग	20 - 21
	3.6	फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी	21 - 22
	3.7	पड़ोसी देशों में कोयला निर्यात	22 - 23
	3.8	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)	23 - 35
4.	**सीआईएल उपलब्धियां**		35 - 62

परिचय

कोयला, प्राथमिक वाणिज्यिक ऊर्जा ईंधन के रूप में, दशकों से देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है और कुछ और दशकों तक भी अपनी प्रासंगिकता बनाए रखेगा। लगभग 55% हिस्सेदारी के साथ, कोयला भारत की ऊर्जा बॉस्केट में प्रमुख स्थान रखता है। देश के नियोजक वैकल्पिक रूप से हरित और नवीकरणीय ऊर्जा रूपों पर जोर दे रहे हैं ताकि बड़े पैमाने पर जीवाश्म संचालित ऊर्जा अर्थव्यवस्था से स्वच्छ स्रोतों द्वारा संचालित अर्थव्यवस्था में स्थानांतरित हो सकें। पर्यावरण की दृष्टि से यह एक स्वागत योग्य कदम है। हालांकि, अक्षय ऊर्जा स्रोतों का प्रवेश निकट भविष्य में कोयले को अस्थिर नहीं करेगा। यह भारत के विद्युत उत्पादन में अपनी प्रमुख भूमिका को जारी रखेगा जैसा कि खपत पैटर्न से संकेत मिलता है।

2020-21 के दौरान अक्षय ऊर्जा स्रोतों सहित कुल 1378.525 बिलियन यूनिट (बीयू) के कुल विद्युत उत्पादन में, कोयला आधारित उत्पादन 950.751 बीयू था जो लगभग **69% है, यह कोयले के महत्व पर प्रकाश डालता है**। इसके अतिरिक्त, कोयला कई गैर-विद्युत उद्योंगों को भी बढ़ावा दे रहा है, जैसे सीमेंट, उर्वरक, स्पंज आयरन, एल्युमीनियम और कई अन्य उद्योग। दुनिया भर के कई देश कोयले से दूर जा रहे हैं लेकिन भारत में परिस्थितियां अलग है। भारत में, जो कोयले को एक पसंदीदा ऊर्जा ईंधन बनाती है, वह है इसकी प्रचुरता, उपलब्धता और वहनीयता। जब तक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत महत्वपूर्ण योगदान देना शुरू नहीं करते, तब तक देश के अपूरणीय प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में कोयले का कोई विकल्प नहीं है।

भारतीय ऊर्जा क्षेत्र में कोयले की एसी प्रमुखता के साथ, कोयला मंत्रालय देश के कोयला उत्पादन में सबसे आगे है।

कोयला मंत्रालय के पास कोयला और लिग्नाइट भंडार की खोज और विकास के संबंध में नितियों और रणनीतियों को निर्धारित करने, उच्च मूल्य की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी देने और सभी संबंधित मुद्दों को तय करने की समग्र जिम्मेदारी है। मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत, इन प्रमुख कार्यों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अर्थात् **कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों और नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) के माध्यम से किया जाता है**। कोल इंडिया लिमिटेड और नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, के अलावा कोयला मंत्रालय का तेलंगाना सरकार के साथ एक संयुक्त उद्यम भी है, जिसे **सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) कहा जाता है**। तेलंगाना सरकार के पास 51% इक्विटी है और भारत सरकार के पास 49% इक्विटी है।

ओडिशा में महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के भरतपुर क्षेत्र में ईको-फ्रेंडली कोल हैंडलिंग प्लांट

I. कोयला मंत्रालय में सुधार

वर्ष 2015

क. एडीआरएम/एएमआरसीडी

I. कोलया मंत्रालय ने सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों और अन्य केंद्र/राज्य पीएयसू के बीच विवादों को सुलझाने के लिए कोयला मंत्रालय से सचिव स्तर के अधिकारी और संबंधित मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी और संबंधित राज्य के एक सचिव स्तर है अधिकारी की अध्यक्षता में एक एडीआरएम फोरम का गठन किया था।

ii. उपरोक्त पहल इस विचार के साथ थी कि दो सार्वजनिक उपक्रमों (केंद्र/राज्य) को अपने विवादों को सुलझाने के लिए अदालतों में नहीं जाना चाहिए। यह स्पष्ट रूप से संकेत दिया गया था कि एडीआरएम समिति द्वारा विवाद को हल करने के बाद राज्य पीएसयू अदालतों में नहीं जाएगा। एडीआरएम समिति के फैसले के बाद सीआईएल भी कोर्ट नहीं जाएगी।

iii. इस संबंध में, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों के साथ अपने लंबे समय से लंबित विवादों के साथ एडीआरएम फोरम में भाग लिया है। इन पक्षों द्वारा संदर्भित विवादों के आधार पर, एडीआरएम समिति ने 22.09.2015 से अब तक राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों, एनटीपीसी, डीवीसी और सीआईएल की सहायक कंपनियों के साथ 15 बैठकें की और इन सार्वजनिक उपक्रमों के बीच 88 विवादों का समाधान किया

झारखंड में दामोदर नदी के किनारे सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के एन.के.क्षेत्र द्वारा विकसित हरित क्षेत्र

मध्य प्रदेश में नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के जयंत क्षेत्र से रेलवे रेक के जरिये कोयले का परिवहन

iv. एडीआरएम (हरियाणा):- एडीआरएम (हरियाणा) की तीन बैठकें हुई जिनमें 39 विवादों का समाधान किया गया।

ख) कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015

i. माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश/निर्णय दिनांक 25.08.2014 और 24.09.2014 के माध्यम से रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 2012 का 120 और अन्य संबंधित मामलों में 1993 से आवंटित 218 कोयला ब्लॉकों में से 204 कोयला ब्लॉकों के आवंटन को रद्द कर दिया है।

ii. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय और आदेश के आलोक में, केंद्र सरकार द्वारा देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई करना जनहित में आवश्यक माना गया।

iii. साथ ही, यह महसूस किया गया कि स्टील, सीमेंट और विद्युत उपयोगिता जैसे प्रमुख क्षेत्रों में कोयले की भारी कमी को दूर किया जा सकता है, जो देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं।

iv. इसके अलावा, घरेलू उपभोक्ताओं, मध्यम और छोटे उद्यमों, कुटीर उद्योगों की कठिनाइयों को कम करने के साथ-साथ देश में कोयले की कुल कमी को दूर करने और नए आवंटनों को कोयला खानों को आवंटित करके इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए, 30.03.2015 के प्रभाव से सीएमएसपी अधिनियम, 2015 अधिनियमित किया गया था।

v. सीएमएसपी अधिनियम, 2015 के धारा 3ए को सम्मिलित करके खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 और धारा 11ए को प्रतिस्थापित करके कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 में भी संशोधन किया, जिससे राष्ट्रीय हित में कोयला खनन शुरू करने की पात्रता से अंत्य उपयोग के प्रतिबंध को हटा दिया गया।

ग. कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 के तहत खानों का आवंटन

- सीएम (एसपी) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के तहत, 107 कोयला खानों का सफलतापूर्वक आवंटन किया गया है। इन 107 कोयला खानों में से 47 को ई-नीलामी के माध्यम से और 60 को सरकारी कंपनियों को आवंटित किया गया है। इन 107 कोयला खानों में से कोयले की बिक्री के लिए 48 कोयला खानों को विनियमित क्षेत्र यानी विद्युत, 22 कोयला खानों को गैर-विनियमित क्षेत्र (एनआरएस) यानी लोहा और इस्पात, सीमेंट और कैप्टिव पावर के साथ-साथ 37 कोयला खानों को आवंटित किया गया है।
- सीएमएसपी अधिनियम, 2015 के तहत आवंटित खानों से वित्तीय वर्ष वार कोयला उत्पादन नीचे दिया गया है :-

वित्तीय वर्ष	मिलियन टन में कोयला उत्पादन
2015-16	**11.81**
2016-17	15.31
2017-18	16.20
2018-19	25.10
2019-20	30.76
2020-21	37.50

घ. सीएम (एसपी) अधिनियम, 2015 के तहत कोयला खानों के आवंटन के लिए सीसीईए द्वारा अनुमोदित कार्यप्रणाली

- सीसीईए द्वारा **निर्दिष्ट अंत्य उपयोग के लिए कोयला खानों / ब्लॉकों की नीलामी और आवंटन के** लिए फ्लोर/रिजर्व मूल्य तय करने की पद्धति को 24.12.2014 को अनुमोदित किया गया था और इस संबंध में आदेश 26.12.2014 को जारी किया गया था।
- **कोयले की बिक्री के लिए कोयला खानों / ब्लॉकों के आवंटन के लिए** अग्रिम भुगतान और आरक्षित मूल्य तय करने की पद्धति को सीसीईए द्वारा दिनांक 16.12.2015 को अनुमोदित किया गया था और इस संबंध में आदेश 08.01.2016 को जारी किया गया था।
- **कोयला / लिग्नाइट की बिक्री के लिए कोयला और लिग्नाइट खानों / ब्लॉकों की नीलामी की** प्रणाली और कोकिंग कोल लिंकेज की अवधि को सीसीईए द्वारा 20.05.2020 को अनुमोदित किया गया है और आदेश 28.05.2020 को जारी किया गया है। मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :
- राजस्व शेयरिंग तंत्र पर आधारित।
- फ्लोर प्रतिशत 4% पर। 0.5% के गुणकों में 10% तक के राजस्व हिस्से तक और उसके बाद 0.25% के गुणकों में बोली वृद्धि।
- पूरी तरह से खोजे गए और साथ ही आंशिक रूप से खोजे गए कोयला ब्लॉकों पर लागू।
- अग्रिम राशि अनुमानित भूवैज्ञानिक भंडार के मूल्य पर आधारित है।

- सफल बोलीदाता को उद्धृत राजस्व हिस्सेदारी, कोयले की कुल मात्रा और काल्पनिक या वास्तविक मूल्य जो भी अधिक हो, के आधार पर मासिक राजस्व हिस्सेदारी का भुगतान करना होगा।
- कोयले के शीघ्र उत्पादन, गैसीकरण और द्रवीकरण के लिए प्रोत्साहन।
- सीबीएम के दोहन की अनुमति है।
- सबसे अधिक बोली लगाने वाला वरीय बोलीदाता होगा।
- कोयले की बिक्री और / या उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं। कोयला उत्पादन अनुसूची में अधिक लचीलापन।

ङ. कोयला परियोजना निगरानी पोर्टल ईसीपीएमपी पोर्टल 2015 में चालू कोयला परियोजनाओं की ऑनलाइन निगरानी के लिए शुरू किया गया था

वर्ष 2016

1. गैर-विनियमित क्षेत्र के लिए कोयला लिंकेज :

2016 में, गैर-विनियमित क्षेत्र के लिए कोयला लिंकेज की नीलामी पर एक नई नीति पेश की गई थी। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं :

- नीलामी के आधार पर सभी लिंकेज,
- मौजूदा ईंधन आपूर्ति समझौते (एफएसए) का कोई नवीनीकरण नहीं [सीपीएसई और उर्वरक (यूरिया) को छोड़कर],
- नए एफएसए 15 साल की अधिकतम अवधि के लिए होंगे,
- सीआईएल ने अब तक लिंकेज नीलामी के चार चरणों को पूरा किया है, और
- पांचवॉं चरण चल रहा है। इन नीलामियों के तहत अब तक 130.19 एमटीपीए कोयला लिंकेज बुक किए जा चुके हैं।

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के मध्य प्रदेश स्थित पेंच क्षेत्र की टाउनशिप के आसपास फैली हरियाली

मध्य प्रदेश में नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के जयंत क्षेत्र में विकसित रोज गार्डन

2. ब्रिज लिंकेज पॉलिसी

2016 में, केंद्रीय और राज्य सार्वजनिक उपक्रमों (दोनों विद्युत के साथ-साथ गैर-विद्युत क्षेत्र में) के निर्दिष्ट अंत्य उपयोग संयंत्रों को ब्रिज लिंकेज प्रदान करने की नीति, जिन्हें कोयला खानें/ब्लॉक आवंटित किए गए हैं, को 08.02.2016 को जारी किया गया था।

- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निर्दिष्ट अंतिम उपयोग संयंत्र की कोयले की आवश्यकता और संबद्ध आबंटिती कोयला खान से उत्पादन की शुरुआत के बीच की खाई को पाटने के लिए अल्पावधि लिंकेज।
- ब्रिज लिंकेज को कोयला खान/ब्लॉक के आवंटन की तारीख से तीन साल की निश्चित अवधि के लिए प्रदान किया जाता है।
- 37 सार्वजनिक उपक्रमों ने 43,100 मेगावाट क्षमता के लिए ब्रिज लिंकेज प्रदान किया।

वर्ष 2017

1. एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के तहत 11 कोयला और 2 लिग्नाइट ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। इन ब्लॉकों को केंद्र / राज्य सरकार की कंपनियों को आवंटन के माध्यम से आवंटित किया गया है। साथ ही, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को कोयले की बिक्री के लिए 89 कोयला ब्लॉकों की निलामी के लिए निर्देश जारी किए हैं, जिनमें से 7 कोयला ब्लॉकों की सफलतापूर्वक एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के तहत नीलामी की गई है।

2. सीबीए नियम, 2017 (अधिसूचित शून्य जीएसआर 877 (ई) दिनांक 13.07.2017)

- सीबीए नियम, 2017 ने पुराने 2012 के नियमों में किए गए विभिन्न संशोधनों को समेकित किया और 2012 के नियमों को प्रतिस्थापित किया।
- नियम कोयला खान (विशेष प्रावधान) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुरूप बनाए गए हैं ताकि कोयला ब्लॉक/खानों के आवंटन के लिए एक समान कानूनी व्यवस्था हो।
- नियम यूएमपीपी के लिए कोयला ब्लॉकों के आवंटन की सुविधा के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए यूएमपीपी के लिए नए मानक बोली दस्तावेज के प्रावधानों को समायोजित करते हैं।
- नियमों में कहा गया है कि कोयला ब्लॉकों की नीलामी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की जाएगी।
- नियमों में कोयले की बिक्री (वाणिज्यिक खनन) के लिए कोयला ब्लॉकों की नीलामी का प्रावधान है।

3. सार्वजनिक हित में एक ही अंत्य उपयोग और लागत दक्षता हासिल करने के लिए कोयला खान के इष्टतम उपयोग के लिए सीएम (एसपी) अधिनियम, 2015 के तहत आवंटित कोयला खानों से निकाले गए कोयले के उपयोग में कुछ लचीलेपन के साथ विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के कोयला ब्लॉक आवंटित करने के लिए इस मंत्रालय द्वारा एक कार्यप्रणाली तैयार की गई थी। इस कार्यप्रणाली को 22.09.2017 को जारी की गई थी।

वर्ष 2018

A. कोयला खान निगरानी और प्रबंधन प्रणाली (सीएमएसएमएस) और 'खान प्रहरी' ऐप

i. अनधिकृत कोयला खनन गतिविधियों की निगरानी के लिए 4 जुलाई 2018 को कोयला खान निगरानी और प्रबंधन प्रणाली (सीएमएसएमएस) और 'खान प्रहरी' ऐप लॉन्च किया गया है।

ii. कोयला खान निगरानी और प्रबंधन प्रणाली (सीएमएसएमएस) एक वेब आधारित एप्लिकेशन है जिसका उपयोग कोलफील्ड क्षेत्रों में लीजहोल्ड सीमाओं के भीतर की जा रही किसी भी प्रकार की अवैध कोयला खनन गतिविधियों का पता लगाने, निगरानी करने और कार्रवाई करने के लिए किया जा सकता है।04.07.2018 को लॉन्चिंग के दौरान, ऐप के बारे में अधिक जागरूकता फैलाने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आमंत्रित किया गया था।

ओडिशा में महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के लखनपुर क्षेत्र में सीड बॉल के जरिये पौधारोपण

iii. यह राष्ट्रीय भू-सूचना विज्ञान केंद्र (एनसीओजी) के मंच का उपयोग करता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) का एक मंच है। इस मंच पर भारत का ग्राम स्तरीय जीआईएस मानचित्र पहले से ही उपलब्ध है जिसका उपयोग विभिन्न सरकारी विभागों के ई-गवर्नेंस अनुप्रयोगों के लिए किया जा रहा है। कोयला खनन संबंधी जानकारी स्तरों के रूप में प्रदान की गई है। वर्तमान में इस प्रणाली पर उपलब्ध स्तर हैं – कोलफील्ड सीमाएं, भूवैज्ञानिक कोयला ब्लॉकों की सीमाएं (सीआईएल और एससीसीएल), लीजहोल्ड सीमाएं और भूमि सुधार की सूचना/रिपोर्ट।

iv. अवैध कोयला खनन गतिविधि का 2 तरीकों से पता लगाया जा सकता है :

- सैटेलाइट डेटा की स्कैनिंग के माध्यम से – यह सीएमपीडीआई में किया जाएगा, जिसमें किसी भी कोयला खनन गतिविधि का पता लगाने के लिए सैटेलाइट डेटा को स्कैन किया जाएगा जो अधिकृत लीजहोल्ड क्षेत्र के बाहर फैली हुई है।
- 'खान प्रहरी' मोबाइल एप्लिकेशन द्वारा नागरिकों द्वारा रिपोर्ट के माध्यम से – कोई भी नागरिक किसी भी अवैध कोयला खनन गतिविधि को मोबाइल ऐप के माध्यम से टेक्स्ट या जियो -टैग्ड तस्वीरों के रूप में रिपोर्ट कर सकता है।

v. उपरोक्त स्रोतों के माध्यम से उत्पन्न रिपोर्ट स्वचालित रूप से नोडल अधिकारियों को अग्रेषित की जाएगी जिन्हें सीआईएल/एससीसीएल और साथ ही विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया है। नोडल अधिकारी रिपोर्ट की गई गतिविधि का सत्यापन करेंगे और कानून के अनुसार कार्रवाई करने या कानून लागू करने वाली एजेंसियों को सूचित करने के लिए पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने जैसी कार्रवाई करेंगे। की गई कार्रवाई को भी सिस्टम में फीड किया जाएगा ताकि कोई भी व्यक्ति सीएमएसएमएस में शिकायत ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से अपनी शिकायत की स्थिति देख सके। शिकायतकर्ता की पहचान उजागर नहीं की जाएगी।

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के उत्तर प्रदेश स्थित दुधिचुआ क्षेत्र से मेरी-गो-राउंड के जरिये कोयले का परिवहन

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के मध्य प्रदेश स्थित हसदेव क्षेत्र में विकसित अनन्य वाटिका

vi. खान डेटा प्रबंधन प्रणाली पोर्टल (एमडीएमएस पोर्टल) 2018 में कोयला परियोजनाओं के लिए एक ऑनलाइन डेटा भंडार के रूप में लॉन्च किया गया था।

वर्ष 2019

1. सरकार ने कोयला खनन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति की समीक्षा की है, और उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा दिनांक 18.09.2019 को एक प्रेस नोट जारी किया गया है, जिसमें समय-समय पर संशोधित सीएम (एसपी) अधिनियम और एमएमडीआर अधिनियम और इस विषय पर अन्य प्रासंगिक अधिनियमों के प्रावधानों के अधीन संबद्ध प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे सहित कोयले की बिक्री, कोयला खनन गतिविधियों के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है।

2. 2019 में अधिसूचित स्टार रेटिंग नीति की शुरूआत।
   सरकार ने 07.03.2019 को सुरक्षा, पर्यावरण, खनन प्रथाओं, प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, श्रमिकों के कल्याण आदि के संदर्भ में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों की पहचान करने के लिए देश की सभी कोयला खानों के लिए स्टार रेटिंग नीति को मंजूरी दी।

पश्चिम बंगाल में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के झांजरा क्षेत्र में विकसित पार्क

वर्ष 2020

1. खनिज कानून (संशोधन) अधिनियम, 2020

खनिज कानून (संशोधन) अधिनियम, 2020 को भारत के राजपत्र में दिनांक 13.03.2020 (सीएमएसपी अधिनियम) में अधिसूचित किया गया था। इस अधिनियम ने खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) और कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 (सीएमएसपी अधिनियम) को संशोधित किया।

उपरोक्त संशोधन के निम्नलिखित प्रभाव/ अपेक्षित परिणाम हैं :-

- संशोधन ने संयुक्त पूर्वेक्षण लाइसेंस -सह-खनन पट्टे के लिए कोयले और लिग्नाइट ब्लॉकों के आवंटन की अनुमति दी है और नीलामी शर्तों की प्रतिबंधात्मक व्याख्या की संभावना को हटा दिया है।
- उपरोक्त संशोधन यह स्पष्ट करेगा कि जिन कंपनियों के पास कोयला खनन का कोई पूर्व अनुभव नहीं है, लेकिन वे आर्थिक रूप से मजबूत हैं और/या अन्य खनिजों या अन्य देशों में खनन का अनुभव रखते हैं, वे कोयला/लिग्नाइट ब्लॉकों की नीलामी में भाग ले सकती हैं। इसके अलावा, प्रस्तावित संशोधन कोयला क्षेत्र में हाल ही में संशोधित एफडीआई नीति के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करेगा जो कोयले की बिक्री, संबद्ध प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे सहित कोयला खनन गतिविधियों के लिए स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100% एफडीआई की अनुमति देता है।

- स्वयं के उपभोग, बिक्री या किसी अन्य उद्देश्य के लिए अनुसूची II और III कोयला खानों की नीलामी की अनुमति देगा।
- कुछ मामलों में सरकार के पिछले अनुमोदन की अनावश्यक और दोहराव वाली आवश्यकताओं को हटा देगा।
- सीएमएसपी अधिनियम के तहत किए गए आवंटन को समाप्त करने, उनके पुन: आवंटन और मुआवजे के प्रावधानों को सक्षम करने का प्रावधान किया गया है।
- जिन खानों के निहित/आवंटन आदेश को निरस्त कर दिया गया है, उन उत्पादनाधीन खानों के प्रबंधन हेतु नामनिर्दिष्ट अभिरक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।
- सफल बोलीदाता/ आवंटियों को इसकी किसी भी सहायक कंपनी या होल्डिंग कंपनी में खनन किए गए कोयले का उपयोग करने की अनुमति है।
- खानें संबंधित गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के अलावा, खनन कार्यों के लिए कुशल और अकुशल दोनों प्रकार के कर्मचारियों का उपयोग करती हैं। इस प्रकार कोयला वाले राज्यों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजित होंगे।

2. कोयला ब्लॉक आवंटन (संशोधन) नियम, 2020

कोयला ब्लॉक आवंटन (संशोधन) नियमों को खनिज कानून (संशोधन) अधिनियम, 2020 द्वारा किए गए एमएमडीआर अधिनियम में संशोधन के आलोक में 18.05. 2020 के प्रभाव से कोयला ब्लॉक आवंटन (संशोधन) नियम 2020 के तहत संशोधित किया गया है। उक्त संशोधन पीएल-सह-एमएल के लिए कोयला ब्लॉकों के आवंटन की प्रक्रिया के बारे में विवरण प्रदान करने के लिए किए गए हैं।

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के उत्तर प्रदेश स्थित दुधिचुआ कोयला प्रोजेक्ट में फैली हरियाली

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के छत्तीसगढ़ स्थित कोरबा क्षेत्र के अधिभार डंप पर किया गया पौधारोपण

3. कोयला क्षेत्र में एफडीआई :

सरकार ने 18.09.2019 को कोयला खनन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति की समीक्षा की है, जिसमें समय-समय पर संशोधित सीएम (एसपी) अधिनियम, 2015 और एमएम (डीआर) अधिनियम, 1957 और इस विषय पर अन्य प्रासंगिक अधिनियम के प्रावधानों के अधीन कोयले की बिक्री, कोयला खनन गतिविधियों सहित संबद्ध प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे सहित स्वचालित मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति है। संबद्ध प्रसंसस्करण बुनियादी ढांचे में कोल वाशरी, कोल हैंडलिंग और पृथक्करण (चुंबकीय और गैर-चुंबकीय) शामिल हैं।

4. कोल लिंकेज में आनुपातिक कमी के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया :

आवंटित कोयला खानों/ब्लॉकों से कोयले की आवश्यकता के आधार पर आवंटित कोयला ब्लॉक को कोयला लिंकेज में आनुपातिक कमी के लिए एक मानक प्रचालन प्रक्रिया तैयार की गई है और 14.02.2020 को जारी की गई है।

5. खनन योजना एवं खान बंद करने की योजना तैयार करने एवं अनुमोदन हेतु संशोधित दिशा-निर्देश दिनांक 29.05.2020 को जारी किया गया। अब, इसे एसडब्ल्यूसी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा और अनुमोदित किया जा रहा है।

6. खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 2020 (एमसीआर) में परिवर्तन और संशोधित एमसीआर 2020 को 29.05.2020 को अधिसूचित किया गया- "खनन योजना और खान बंद करने की योजना की तैयारी और अनुमोदन के लिए संशोधित दिशानिर्देश" जारी करने के उद्देश्य से खनिज रियायत नियम (एमसीआर) में संशोधन खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 2020 के रूप में बनाए गए।

वर्ष 2021

1. संपत्ति मुद्रीकरण योजना :

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना के लिए नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित लक्ष्य 3394 करोड़ रुपये है , जिसके लिए कोयला मंत्रालय ने अब तक 19,915.15 करोड़ रुपये की राशि हासिल की है।

2. 14. कोलियरी नियंत्रण (संशोधन) नियम, 2021 (राजपत्र जीएसआर 546 (ई) दिनांक 09.08.2021 के तहत अधिसूचित) :

विभिन्न अनुपालनों की प्रासंगिकता और आवश्यकता की जांच करने के साथ-साथ समानांतर अनुपालनों को दूर करके व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ाने के लिए संबंधित प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत, कम करने और सरल बनाने के उद्देश्य से, सीएमसीडी अधिनियम और सीएमसीडी नियमों को एक अधिनियम को अनुपालन बोझ से कम करते हुए निरस्त कर दिया गया है। और सीसीआर, 2004 को कोलियरी नियंत्रण (संशोधन) नियम, 2021 में संशोधित किया गया है, जिसे भारत के राजपत्र में जीएसआर 546 (ई) दिनांक 09.08.2021 के माध्यम से अधिसूचित और प्रकाशित किया गया है।

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के उत्तर प्रदेश स्थित कृष्णशिला क्षेत्र में ईको-फ्रेंडली बेल्ट पाइप कन्वेयर के जरिये कोयला परिवहन

3. कैप्टिव कोयला खानों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित 50% कोयले की बिक्री की अनुमति देने वाला उदारीकरण – खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 2021 (01.10.2021 को जीएसआर 717 (ई) के माध्यम से अधिसूचित)

खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 ने एमएमडीआर अधिनियम 1957 में संशोधन किए। उक्त संशोधनों ने खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 1960 में संशोधन की आवश्यकता हुई। इसलिए, एमसीआर, 1960 को खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 2021 के माध्यम से उचित रूप से संशोधित किया गया है।

उक्त संशोधनों का उद्देश्य कैप्टिव खानों के पट्टेदारों को निर्धारित मात्रा में कोयला या लिग्नाइट बेचने की अनुमति देकर खुले बाजार में घरेलू कोयले या लिग्नाइट की उपलब्धता को बढ़ाना है। कोयले या लिग्नाइट की निर्धारित मात्रा में बिक्री के लिए भत्ता भी कैप्टिव पट्टेदारों को कैप्टिव खानों से उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। इसके अलावा, बेचे गए कोयले या लिग्नाइट की मात्रा के संबंध में अतिरिक्त राशि, रॉयल्टी और अन्य वैधानिक भुगतानों के भुगतान से राज्य सरकारों के राजस्व में वृद्धि होगी।

4. विपणन सुधार:

क्रिसिल लिमिटेड को कोल ट्रेडिंग एक्सचेंज की स्थापना की प्रक्रिया में कोयला मंत्रालय की सहायता के लिए रणनीतिक और कार्यान्वयन प्रबंधन परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। देश में कोल ट्रेडिंग एक्सचेंज की स्थापना से ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोयला बाजार खुल जाएगा और बाजार में कोयले की आसानी से उपलब्धता हो जाएगी।

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के उत्तर प्रदेश स्थित खड़िया क्षेत्र का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट

महाराष्ट्र में वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के नागपुर क्षेत्र का महात्मा गांधी ईको-पार्क

5. कोयला खानों में सुरक्षा के उपाय सुझाने और निजी क्षेत्र की कोयला खानों का निरीक्षण करने के लिए सुरक्षा पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है।
6. मिशन कोयला गैसीकरण शुरू किया गया है। कोयले का विविधीकरण और भूतल कोयला गैसीकरण की अवधारणा की शुरूआत- सीआईएल/एनएलसीआईएल में 03 परियोजनाओं में निविदा जारी की गई है और 3 और परियोजनाओं की पहचान की गई है।
7. सीआईएल को अपने कमान क्षेत्र से सीबीएम निकासी की अनुमति देना। एमओपी एंड एनजी को 2017 में अधिसूचित किया गया। 3 परियोजनाओं की पहचान की गई; एक परियोजना में, बोलीदाताओं का चयन किया गया और अन्य 02 परियोजनाओं के लिए, 3 बार निविदाएं मंगाई गईं, कोई बोली प्राप्त नहीं हुई।
8. कोयला मंत्रालय की एसएंडटी योजना के तहत अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्र की पहचान की गई और भविष्य की अनुसंधान परियोजनाओं के लिए परिचालित किया गया।
9. सीआईएमएफआर, आईआईटी आईएसएम धनबाद, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास जैसे शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों को शामिल करते हुए कोयला गैसीकरण, झरिया फायर डीलिंग और भूमिगत खनन की दिशा में अनुसंधान प्रयासों को बढ़ाने के लिए एक संसाधन समिति का गठन किया गया है ।
10. स्थायी वैज्ञानिक अनुसंधान समिति (एसएसआरसी) की तकनीकी उपसमिति का पुनर्गठन किया गया और शैक्षणिक संस्थान शामिल थे। तकनीकी उप-समिति के अध्यक्ष अब आईआईटी बीएचयू, आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी आईएसएम के बीच रोटेशन पर होंगे।
11. अनुसंधान परियोजनाओं पर सूचना के प्रसार के लिए वेब साइट का विकास।
12. खानों की निगरानी और माप में ड्रोन का परिचय। सीएमपीडीआई द्वारा निष्पादित 2 परियोजनाएं।
13. कोयले से हाइड्रोजन तक का रोडमैप तैयार करने के लिए एक टास्क फोर्स और विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया।
14. एसपीवी, मुख्य रूप से-एमसीआरएल, जेसीआरएल, सीईआरएल और सीईडब्ल्यूआरएल; झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में कोयला निकासी के लिए रेल परियोजनाओं को लागू करने के लिए स्थापित किया गया है। कोयले की निकासी के लिए 14 रेल परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं।

II. कोयला मंत्रालय में उपलब्धियां

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के छत्तीसगढ़ स्थित दीपका क्षेत्र में कार्यरत फॉग कैनन

• 1. वाणिज्यिक खनन

अब तक, कुल 105 कोयला ब्लॉक जिनकी कुल अधिकतम रेटेड क्षमता। 512 एमटी/वार्षिक और लगभग 15,000 मीट्रिक टन के भूवैज्ञानिक रिजर्व को नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा आवंटित किया गया है [105 सीएमएसपी अधिनियम, 2015 के तहत और 18 एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के तहत]। इसमें से 47 कोयला खानों को खान खोलने की अनुमति मिल गई है, जिनमें से 36 कोयला ब्लॉक वास्तव में उत्पादन कर रहे हैं।

कोयला ब्लॉक आवंटन स्थिति (सीएमएसपी ब्लॉक)		पीआरसी (मि.ट)
आवंटित खानों की कुल संख्या	105	512.07
खान खोलने की अनुमति (एमओपी) वाली खानें	47	171.55
जिन खानों को खान खोलने की अनुमति नहीं है	58	340.52
खान खोलने की अनुमति प्राप्त 47 खानों में से, कोयला उत्पादन के अधीन खानें	36	128.95
नई खानों को 2022-23 में खान खोलने की अनुमति मिलने की संभावना ह	11	57.57
नई खानों में 2022-23 में कोयला उत्पादन शुरू होने की संभावना	12	54.27

कोयला ब्लॉक आवंटन स्थिति (एमएमडीआर ब्लॉक)		पीआरसी (मि.ट.)
आवंटित खानों की कुल संख्या	18	41.87 (7 खानों के लिए)
खान खोलने की अनुमति वाली खानें	0	0

2. कोयला आयात प्रतिस्थापन:

कोयला आयात प्रतिस्थापन के उद्देश्य से दिनांक 29.05.2020 को कोयला मंत्रालय में एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया गया है। विद्युत मंत्रालय, रेल मंत्रालय, जहाजरानी मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के प्रतिनिधि (सीईए), कोयला कंपनियां और बंदरगाह इस आईएमसी के सदस्य हैं। आईएमसी की अब तक 9 बैठकें हो चुकी हैं। आईएमसी के निर्देश पर, कोयला मंत्रालय द्वारा एक आयात डेटा विकसित किया गया है ताकि मंत्रालय कोयले के आयात को ट्रैक कर सके। कोयले की अधिक घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कोयला आयात प्रतिस्थापन के कार्य को अगले स्तर तक ले जाने के लिए, कोल इंडिया लिमिटेड को 2023-24 तक शुन्य कोयला आयात मिशन की योजना बनाने के लिए कहा गया है। एस प्रकार, पूरे प्रतिस्थापन योग्य आयातित कोयले की पूर्ति देश द्वारा की जानी चाहिए और अति आवश्यक के अलावा कोई आयात नहीं होना चाहिए। कोल इंडिया लिमिटेड को कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया गया है।

नॉर्दर्न कोलफील्डस लिमिटेड के मध्य प्रदेश स्थित निगाही क्षेत्र में कार्यरत वॉटर स्प्रिंकलर

घरेलू और आयातित कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों, दोनों के लिए विद्युत क्षेत्र द्वारा कोयले का आयात अप्रैल-दिसंबर, 2021 की अवधि के दौरान पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 39% कम हुआ है।

विगत आठ वर्षो 2013-14 से 2020-21 के दौरान कोयले के आयात का विवरण इस प्रकार है:-

2013-14 से 2021-22 तक (नवंबर 2021 तक) कोयले का देश-वार आयात

(मात्रा मिलियन टन में और मूल्य मिलियन रुपये में)

वर्ष	कोकिंग कोल		गैर कोकिंग कोल		कुल कोयला	
	मात्रा	मूल्य रु.	मात्रा	मूल्य रु.	मात्रा	मूल्य रु.
2013-14	36.872	348318.65	129.985	574973.16	166.857	923291.81
2014-15	43.715	337655.59	168.388	707585.71	212.103	1045241.30
2015-16	44.561	282519.09	159.388	577818.53	203.949	860337.62
2016-17	41.644	412300.61	149.365	590772.69	191.009	1003073.30
2017-18	47.003	595226.36	161.245	789543.41	208.249	1384769.77
2018-19	51.838	720497.64	183.510	988707.26	235.348	1709204.90
2019-20	51.833	612668.32	196.704	914652.23	248.537	1527320.55
2020-21	51.198	453552.10	164.054	706688.44	215.251	1160240.54
2021-22 (नवंबर 21)	39.780	580134.18	107.363	772412.34	147.143	1352546.52
2020-21 (नवंबर 20)	29.736	267746.43	104.817	430607.76	134.553	698354.19
वृद्धि %	33.776	116.67	2.429	79.38	9.357	93.68

स्रोत : भारत की प्रकाशित सीसीओ निर्देशिका 202-21

3. विद्युत क्षेत्र लिंकेज नीति-शक्ति

सरकार ने मौजूदा आश्वासन पत्र (एलओए) - ईधन आपूर्ति समझौते (एफएसए) प्रणाली को खत्म करने की मंजूरी दी और भारत में पारजर्शी रुप से कोयले के दोहन और आवंटन के लिए योजना (शक्ति), 2017 की शुरुआत की, जिसे कोयला मंत्रालय द्वारा 22.05.2017 को जारी किया गया था। सरकार ने शक्ति नीति, 2017 में संशोधन को भी मंजूरी दी, जिसे कोयला मंत्रालय द्वारा 25.03.2019 को जारी किया गया था।

अब तक, नीति के विभिन्न पैराओं के तहत निम्नलिखित क्षमताओं के लिए कोयला लिंकेज प्रदान किए गए हैं :

(I) पैरा क (i) के प्रावधानों के तहत 7,210 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 9 एलओए धारकों को ईधन आपूर्ति समझौते (एफएसए) पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी गई है।

(ii) पैरा ख (i) के प्रावधानों के तहत 26000 मेगावाट की कुल क्षमता के लिए 23 ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) को लिंकेज प्रदान किया गया है।

(iii) ख (ii) के तहत लिंकेज नीलामी का पहला दौर सितंबर, 2017 में आयोजित किया गया था, जिसमें लगभग 9,045 मेगावाट क्षमता के लिए दस सफल बोलीदाताओं द्वारा 27.18 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) वार्षिक कोयला लिंकेज बुक किया गया था। मई, 2019 में आयोजित दूसरे दौर में आठ बोलीदाताओं द्वारा लगभग 874.9 मेगावाट क्षमता के लिए 2.97 एमटीपीए लिंकेज की बुकिंग की गई है। तीसरे दौर में, मई, 2020 के दौरान पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल) द्वारा नीलामी आयोजित की गई है, जहां 5 सफल बोलीदाताओं द्वारा 2.8 एमटीपीए लिंकेज बुक किए गए हैं। पीएफसीसीएल द्वारा सितंबर, 2021 में चौथे दौर की लिंकेज नीलामी आयोजित की गई है, जहां 5 सफल बोलीदाताओं द्वारा 3.20 एमटीपीए लिंकेज बुक किए गए हैं।

(iv) शक्ति ख (iii) के लिए लिंकेज नीलामी फरवरी, 2020 में आयोजित की गई थी, जहां कुल 11.8 एमटीपीए, 6.48 एमटीपीए की बोली 7 सफल बोलीदाताओं द्वारा बुक की गई थी।

(v) शक्ति नीति के ख (iv) के तहत लिंकेज के लिए सीआईएल से गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों के लिए क्रमश: 4000 मेगावाट, 1600 मेगावाट और 2640 मेगावाट की क्षमता के लिए कोल लिंकेज निर्धारित किया गया है।

(vi) ख (v) के तहत लिंकेज के लिए 2500 मेगावाट की क्षमता के लिए सीआईएल से कोयला लिंकेज निर्धारित किया गया है।

(vii) ख (viii) (क) के तहत लिंकेज नीलामी के 8 चरणों का आयोजन किया गया है। कुल 41.13 मीट्रिक टन कोयले की पेशकश की गई मात्रा में से 8.13 मीट्रिक टन सफल बोलीदाताओं द्वारा बुक किया गया है।

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के छत्तीसगढ़ स्थित गेवरा क्षेत्र में कार्यरत ईको-फ्रेंडली 'सरफेस माइनर'

4. कोयला लिंकेज का युक्तिकरण :

विद्युत क्षेत्र (राज्य/केंन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के लिए) में कोयला लिंकेज युक्तिकरण के परिणामस्वरुप खानों से विद्युत संयंत्रों तक परिवहन लागत में कमी आई है जिससे अधिक कुशल कोयला आधारित विद्युत का उत्पादन हुआ है। कोयला मंत्रालय ने 2018 में स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) के लिए लिंकेज युक्तिकरण के लिए नीति जारी की है। 2014 से, अब तक 6931.86 करोड़ रु. वार्षिक संभावित बचत के साथ कुल 98.16 मिलियन टन कोयले का युक्तिकरण किया गया है।

2020 में लिंकेज युक्तिकरण पर एक नई पद्धति तैयार की गई है जिसमें विद्युत क्षेत्र के साथ-साथ गैर-विनियमित क्षेत्र (एनआरएस) शामिल हैं और आयातित कोयले के साथ कोयले की अदला-बदली की भी अनुमति दी गई है।

5. तृतीय पक्ष नमूनाकरण :

कोयले की गुणवत्ता के संबंध में उपभोक्ताओं (विद्युत उपयोगिताओं) की चिंताओं को दूर करने के लिए, कोयला कंपनियों द्वारा आपूर्ति किए गए कोयले की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 2015 में तीसरे पक्ष के नमुने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) शुरु की गई है, जिसके लिए केंद्रीय खनन और ईधन अनुसंधान संस्थान (सीआईएमएफआर, एक सीएसआईआर संस्थान) की कोयला कंपनियों और विद्युत क्षेत्र द्वारा संयुक्त रुप से लगाया गया है। लोडिंग एंड पर कोयले के नमूने और परीक्षण के लिए आपूर्तिकर्ता (कोयला कंपनियों), क्रेता (पावर यूटिलिटीज) और सीआईएमएफआर के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। लिंकेज नीलामी के माध्यम से कोयला लेने वाले गैर-विद्युत उपभोक्ताओं के लिए नमूना सुविधा का विस्तार करने और पावर के लिए विशेष फॉरवर्ड नीलामी के तहत पावर यूटिलिटीज को आपूर्ति करने के लिए, क्यूसीआई और आईआईटी-आईएसएम को लगाया गया है।

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के मध्य प्रदेश स्थित निगाही क्षेत्र में अधिभार डंप पर मिट्टी की ऊपरी परत के संरक्षण का कार्य

नॉर्दर्न कोलफील्डस लिमिटेड के मध्य प्रदेश स्थित निगाही क्षेत्र में किया गया 'कर्टेन प्लांटेशन'

विद्युत और गैर-विद्युत कोयला उपभोक्ताओं, दोनों के लिए तृतीय-पक्ष नमूना एजेंसियो के विकल्पों को बढ़ाने के लिए, मोजूदा तृतीय-पक्ष नमूना एजेंसियों जैसे सीएसआईआर-सीआईएमएफआर और क्यूसीआई के अलावा, सीआईएल सहायक कंपनियों में लोडिंग एंड पर कोयले के नमूने और विश्लेषण का काम करने के लिए 15.03.2021 से दो और पार्टियों को नई तृतीय-पक्ष नमूना एजेंसियो के रुप में सूचीबद्ध किया गया है।

एक सुधार प्रक्रिया के रुप में, यह निर्णय लिया गया है कि विद्युत क्षेत्र के लिए टीपीएस (थर्ड पोर्टी सैंपलिंग) एजेंसियो को पीएफसी द्वारा सूचीबद्ध किया जाएगा। पीएफसी एब सीआईएमएफआर के अलावा एजेंसियों को सूचीबद्ध करेगा और उपभोक्ता किसी भी पैनल में शामिल एजेंसियो की सेवाए लेने के लिए स्वतंत्र होंगे।

6. फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी

हमारे माननीय प्रधान मंत्री के बेहतर शासन के समग्र दृष्टिकोण के अनुरुप **'व्यापार करने में आसानी के साथ रहने में आसानी' की सुविधा के लिए,** फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजना के 'परिवर्तनकारी विचार' का उद्देश्य कोयला खान क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन को आसान बनाना है। भीड़भाड़, सड़क दुर्घटनाएं, कोयला खानों के आसपास पर्यावरण और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव और वैकल्पिक परिवहन विधियों जैसे मशीनीकृत कन्वेयर सिस्टम और रेलवे रेक में कम्प्यूटरीकृत लोडिंग को नियोजित करके कोयला हैंडलिंग दक्षता में वृद्धि करना। कोयला कंपनियों ने खानों में कोयले के सड़क परिवहन को समाप्त करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करने की रणनीति तैयार की है।

- कन्वेयर बेल्ट सिस्टम द्वारा मशीनीकृत कोयला परिवहन के लिए सीआईएल, एससीसीएल और एनएलसीआईएल के लिए तैयार की गई एफएमसी; परियोजना मौजूदा 151 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) से 2023-2024 तक 609 एमटीपीए।

झारखंड में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के कतरास क्षेत्र में विकसित ईको-पार्क 'पारसनाथ उद्यान'

- 2019 में 39 परियोजनाओं (458 एमटीपीए) की पहचान की गई। इन परियोजनाओं की स्थिति नीचे दी गई है :

कमीशन	टेस्ट रन के तहत	निविदा प्रदान की गई / निर्माणाधीन	फिर से निविदा निकाली गई	लंबित परियोजनाएं
6	1	30	1	1

- वित्तीय वर्ष 2021-22 की शेष अवधि में 3 और एफएमसी परियोजनाएं (35 एमटीपीए) चालू होने वाली हैं।

- 2022-23 में 18 एफएमसी परियोजनाएं चालू की जाएंगी।

7. पड़ोसी देशों में कोयले का निर्यात

सीआईएल को सुझाव दिया गया है कि निर्यात के उद्देश्य से कोयले की बिक्री के लिए सीआईएल की विशेष स्पॉट ई-नीलामी/स्पॉट ई-नीलामी विंडो का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, जिस कोयले का घरेलू बाजार में उपयोग/बिक्री नहीं की जा सकता है, उसका ही निर्यात किया जाना चाहिए। सीआईएल घरेलू मांग को पूरा करने के बाद कोयले के निर्यात के लिए पड़ोसी देशों द्वारा मंगाई गई निविदाओं में भी भाग ले सकती है। इसके अलावा, पड़ोसी देशों के व्यापारी/कोयला उपभोक्ता भी सीआईएल की विशेष स्पॉट ई-नीलामी/स्पॉट ई-नीलामी विंडो मे भाग ले सकते हैं।

उपरोक्त के अनुसरण में, सीआईएल द्वारा आयोजित नीलामी आयोजनों के तहत कोयले के निर्यात की अनुमति इच्छुक बोलीदाताओं को कोयले के निर्यात के लिए और विकल्प प्रदान करने की है, यदि वे देश के भीतर ऐसे कोयले की बिक्री के अलावा ऐसा करना चाहते हैं। सुविधा के बाद, सफल बोलीदाता नीलामी योजना के तहत कोयले की खरीद कर सकते हैं और अपने स्वयं के नेटवर्क/तंत्र के माध्यम से निर्यात कर सकते है।

इसके अलावा, पड़ोसी देशों द्वारा मंगाई गई निविदाओं में भाग लेने के लिए, सीआईएल भविष्य में घरेलू मांग-आपूर्ति परिदृश्य और निविदा में इंगित कोयले की तकनीकी विशिष्टताओं को ध्यान में रखने हुए निर्णय लेगी।

8. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

क. कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और उसकी सहायक कंपनियां

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2013-14	वित्तीय वर्ष 2014-15	वित्तीय वर्ष 2015-16	वित्तीय वर्ष 2016-17	वित्तीय वर्ष 2017-18	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2020-21
सीएसआर व्यय (करोड़ रुपये)	409.37	298.10	1076.07	489.67	483.78	416.47	587.84	553.85

2013-14

- 2013-14 के दौरान, सीएसआर व्यय 409.37 करोड़ रु.

2014-15

- **सीएसआर-कोल इंडिया और उसकी सहायक कंपनियों ने सीएसआर पहल पर वित्त वर्ष 2015 में 298.10 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।**
- **कुछ प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं :**
  - 30,340 स्कूलों में स्वच्छ विद्यालय अभियान के माध्यम से 48,735 शौचालयों के निर्माण।
  - टाटा मेडिकल सेंटर (टीएमसी) के साथ समझौते ने प्रेमाश्रय के निर्माण के लिए 41.11 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं ''एक दस मंजिला इमारत जो इलाज के लिए टीएमसी में आने वाले आर्थिक रुप से कमजोर बाहरी रोगियों के लिए आवास की सुविधा प्रदान करती है।

झारखंड में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के रजरप्पा क्षेत्र में किया गया ईको-रेस्टोरेशन कार्य

झारखंड के धनबाद में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा विकसित पंचवटी ईको-पार्क का एरियल दृश्य

- पश्चिम बंगाल के पिछडे जिले पुरुलिया के 40 गांवों में विकास कार्यो के निष्पादन के लिए 32.92 करोड़ रुपये की परियोजना लागत पर ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टीईआरआई) के साथ समझौता ज्ञापन।
- परियोजना के लिए 6.40 करोड़ रुपये के योगदान के साथ पीपीपी मॉडल पर औद्योगिक भागीदारों में से एक के रुप में कल्याणी में एक भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटि) की स्थापना।
- **कोल इंडिया ने निम्नलिखित का भी निधियन किया–**
    - अलीपुरद्वार नगर पालिका, पश्चिम बंगाल के वंचित लोगों के लिए 78.40 लाख रुपये की लागत से जल उपचार संयंत्र की स्थापना के लिए।
    - रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम, मुजफ्फरपूर, बिहार में 4.93 करोड़ रु. की लागत से 100 बिस्तरों वाले चेरिटेबल आई, कान और जीभ/दंत/डाइग्रोस्टिक केन्द्र के निर्माण के लिए।
    - ग्रामीण आबादी में जागरुकता कार्यक्रमों के माध्यम से प्रचार और निवारक स्वास्थ्य देखभाल के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लार्जर अवेयरनेस (एनआईएलए), असम जहां साक्षरता कम है, जिसकी लागत 31.51 लाख रुपये है।
    - नेशनल चैरिटेबल सोसाइटी, प्रतापगढ़, यूपी में 50 सौर ऊर्जा संचालित स्ट्रीट लाइट और 50 हैंड पंपों की स्थापना के लिए 30.45 लाख रूपये। सुनेबेड़ा क्षेत्र विकास एजेंसी (एसएडीए), ओडिशा, 3.60 करोड़ रू. की लागत से 12000 परिवारों को साइकिल उपलब्ध कराने के लिए।

2015-16

- **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व :** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसरण में सीएसआर पर कुल व्यय रु. 1076.07 करोड़ और नेपाल भूकंप राहत कोष में रु. 6.00 करोड़ रुपये 1082.07 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं।

  कुछ प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं :

  - 53,412 शौचालयों का निर्माण कर स्वच्छ विद्यालय अभियान की दिशा में पहल। इन शौचालयों के निर्माण पर 31 मार्च, 2016 तक कुल 820.44 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।
  - 1.14 करोड़ रुपये की लागत से कोलकाता में जलीय खेल छात्रावास का निर्माण।
  - यातायात विभाग, कोलकाता पुलिस 69.85 लाख रू. की लागत से सड़क सुरक्षा के प्रति स्कूली बच्चों के बीच जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए।
  - पश्चिम बंगाल आवासीय अवसंरचना विकास निगम कोलकाता को 5 करोड़ रूपये की लागत से 3 इेलक्ट्रिक बसें और 1 छोटा इलेक्ट्रिक सर्विस मेंटेनेंस व्हीकल खरीदने के लिए।
  - स्कुल शिक्षा विभाग, पश्चिम बंगाल, सरकार के दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना और नदिया जिले पश्चिम बंगाल में छात्राओं को 2.88 करोड़ रू. की लागत से 9,000 साइकिलें प्रदान करने के लिए।

2016-17

- **कोल इंडिया ने वित्त वर्ष 2017 के अंत में सीएसआर पहलों पर 489.67 कड़ोर रूपये खर्च किए हैं।** की गई प्रमुख गतिविधियाँ निम्नलिखित हैं :

  - युवा मामलों ते मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से 75 करोड़ रुपये (25 करोड़ रुपये प्रति वर्ष) के परियोजना परिव्यय पर ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों का प्रशिक्षण और तैयारी।

पश्चिम बंगाल में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के झांजरा क्षेत्र में विकसित ईको-पार्क

➢ 65 करोड़ रूपये के परिव्यय से 10 शहरों में 16 सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों की स्थापना।

2017-18

- कोल इंडिया ने वित्त वर्ष 2018 के अंत में **सीएसआर पहल पर** 483.78 कड़ोर रूपये खर्च किए हैं।

  की गई प्रमुख गतिविधियाँ निम्नलिखित हैं :

  ➢ क्रिश्चियान मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर, टाटा मेडिकेल सेंटर, कोलकाता, राजीव गांधी कैंसर संस्थान और अनुसंधान केंद्र, नई दिल्ली, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली और पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़ को प्रति रोगी 10 लाख रूपये की वित्तीय सहायता के माध्यम से थैलेसीमिया रोगियों में बीमारी का इलाज और बेहतर प्रबंधन।

  ➢ ऊर्जा संसाधन संस्थान (टेरी) के माध्यम से पुरुलिया, पश्चिम बंगाल में विभिन्न विकास कार्य :

    ❖ घरों की उर्जा जरुरतों के लिए नवीकरणीय समाधानों को बढ़ाबा देना-एकीकृत घरेलू उर्जा प्रणालियों और सौर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना।

    ❖ कृषि, हरित और क्षमता निर्माण पहलें।

    ❖ स्वच्छता-5,660 घरों में व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण।

    ❖ 40 विद्यालयों में ज्ञान एवं संसाधन केन्द्रों के माध्यम से शिक्षा।

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के उत्तर प्रदेश स्थित ककरी क्षेत्र में अधिभार डंप पर किए गए पौधारोपण से फैली हरियाली

ओडिशा में महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के लखनपुर क्षेत्र में कार्यरत फॉग कैनन

- ➢ मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का निर्माण–एमसीएल द्वारा तालचेर, ओडिशा में महानदी इंस्टीट्युट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च (एमआईएमएसआर)।
- ➢ सीमीएल के लाल/सीसीएल की लाडली–आईआईटी, एनआईटी और देश के अन्य प्रतिष्ठित कॉलेजों में प्रवेश के लिए उपस्थित होने के लिए सीसीएल के कमांड क्षेत्रों में रहने वाले पीएपी (परियोजना प्रभावित लोगों) के मेधावी छात्रों को 10 वीं और 12 वीं कक्षा के लिए आवास, बोर्डिंग और औपचारिक स्कूली शिक्षा के साथ विशेषज्ञों से कोचिंग प्रदान करके सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से एक पहल।
- ➢ एसईसीएल द्वारा ग्रीन हाईवे को अपनाना – एनएच–78 के साथ शहडोल से मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़ सीमा तक सड़क किनारे वृक्षारोपण (लगभग 100 किमी) एनएचएआई के माध्यम से कार्यान्वित किया गया।
- ➢ बीसीसीएल द्वारा मोबाइल मेडिकल वैन के माध्यम से ग्रामीणों का उपचार – 1.19 लाख से अधिक लाभार्थी।
- ➢ महंगे चिकित्सा उपकरणों की खरीद के माध्यम से सीआईएल द्वारा कोलकाता में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड डाइजेस्टिव साइंसेज (आईआईएलडीएस) की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता।

2018-19

- वित्तीय वर्ष में बुक किया गया सीएसआर व्यय 416.47 करोड़ रुपये था।
  - ➢ सीएसआर परियोजना "थैलेसीमिया रोगियों में बीमारी का इलाज और बेहतर प्रबंधन" के तहत गरीब मरीजों को राहत देते हुए छह प्रमुख अस्पतालों में जून, 2019 तक 105 अस्थि मज्जा प्रत्याहरोपण ऑपरेशन किए गए हैं।

झारखंड में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के एन.के. क्षेत्र में विकसित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग-सह-मतस्य पालन केंद्र

- ➢ पुरुलिया जिले में टेरी की ग्रामीण विकास परियोजना की एक अन्य प्रमुख परियोजना है। अब तक 8,891 सोलर होम लाइटिंग सिस्टम, 100 सोलर स्ट्रीट लाइट, 7,342 बेहतर कुक स्टोव लगाए जा चुके हैं। स्वच्छता के क्षेत्र में जून 2019 तक लगभग 5,500 शौचालयों का निर्माण पूरा हो चुका है।
- ➢ झारखंड के गोड्डा में 300 बिस्तरों वाले अस्पताल को वित्तीय महायता प्रदान की गई है। ओडिशा में सीआईएल की सहायक कंपनी की वित्तीय सहायता से तालचेर में एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बन रहे हैं।

2019-20

- **सीआईएल और उसकी अनुषंगियों ने 2019-20 के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर 587.84 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।** सीआईएल ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास के लिए निम्नानुसार महत्वपूर्ण योगदान दिया है :
  - ➢ चक्रवात फानी के कारण क्षतिग्रस्त हुई विद्युत पारेषण लाइनों को पुन:स्थापित करने के लिए ओडिशा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओपीटीसीएल) को 50.32 करोड़ रु.।
  - ➢ कर्नाटक के धारवाड़ और बागलकोट जिलों में बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुए सरकारी स्कूल भवनों के पुनर्निर्माण के लिए 25 करोड़ रु.।
  - ➢ असम के बाढ़ प्रभावित माजुली जिले में आजीविका पुनर्वास परियोजना और जल एम्बुलेंस की खरीद के लिए 16.50 करोड़ रुपये रु.।
  - ➢ कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए पीएम केयर्स फंड में 160 करोड़ का योगदान दिया।
  - ➢ सीआईएल की दो सहायक कंपनियों, सीसीएल को खेल को बढ़ावा देने के लिए और एमसीएल को स्वास्थ्य, सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में योगदान के लिए भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

2020-21

- सीआईएल और उसकी अनुषंगियों ने सीएसआर गतिविधियों पर 553.85 करोड़ रु. खर्च किए हैं, वर्ष के कुल खर्च किए गए सीएसआर में से, 48.57% विशेष रूप से खनन क्षेत्रों की निकटता वाले समुदाय के लाभ के लिए कोविड राहत उपायों पर खर्च किया गया था।

  - लगभग 1,500 बिस्तरों की स्थापना इसे भारतीय कॉरपोरेट्स के बीच सबसे बड़े मोविलाइजर्स मेम से एक बनाती है।
  - सीएमआर के प्रयास महामारी की दूसरी लहर के दौरान लगातार जारी रहे और साथ ही कुल बिस्तरों की संख्या दोगुनी से अधिक 3,900 हो गई।
  - अपने और सरकारी अस्पतालों सहित 27 अस्पतालों में 29 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करने का निर्णय।
  - एमसीएल नेभुवनेश्वर में 525 बिस्तरों का अस्पताल और लखनपुर में 150 बिस्तरों का अस्पताल स्थापित किया हे।
  - सीआईएल ने एसईसीएल के अंतर्गत अंबिकापुर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में सरकारी अस्पतालों को कोविड उपचार केन्द्रों में बदल दिया है एसईसीएल और कर्नाटक के धारावाड़ में एक अन्य अस्पताल को 100 बिस्तरों वाले कोविड उपचार केन्द्र में परिवर्तित किया है।
  - एनसीएल ने उत्तर प्रदेश सरकार को 50 एम्बुलेंस प्रदान की हैं।
  - जरूरतमंद समुदाय को 3 लाख से अधिक मुफ्त भोजन के पैकेट, 17.56 लाख से अधिक मास्क और 80,800 लीटर से अधिक हैंड सैनिटाइजर का वितरण किया।

झारखंड में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के रजरप्पा क्षेत्र पौधारोपण के जरिये विकसित जंगल

ख. एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) और इसकी सहायक कंपनियां

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2013-14	वित्तीय वर्ष 2014-15	वित्तीय वर्ष 2015-16	वित्तीय वर्ष 2016-17	वित्तीय वर्ष 2017-18	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2020-21
सीएसआर व्यय (करोड़ रुपये)	26.30	47.49	81.93	37.91	45.03	53.16	89.75	52.79

पिछले 8 वर्षों के दौरान एनएलसीआईएल की समेकित सीएसआर प्रमुख गतिविधियां :

I. पांच अलग-अलग राज्यों के विभिन्न अस्पतालों में 28 ऑक्सीजन संयंत्रों का निर्माण।

ii. विभिन्न अस्पतालों को 450 ऑक्सीजन सांद्रक दिए गए।

iii. स्कूल शिक्षा आयुक्त, तमिलनाडु सरकार के माध्यम से सीएसआर गतिबिधियों के तहत सरकारी स्कूलों में व्यक्ति के लिए सीखने के त्वरण के लिए सहायता (एएलएआई) में सुधार के लिए योगदान राशि।

iv. नदी की सफाई और गाद निकालना और टैंकों को गहरा करना।

v. आकांक्षी जिले, रामनाथपुरम के एट्टीवायल गांव में ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू किया गया।

vi. तूतीकोरिन के आसपास के गांव के उन लोगों को राहत सामग्री खाद्यान्न और किराने का सामान उपलब्ध कराने पर व्यय किया गया जिनकी आजीविका कोविड-19 लॉक डाउन से प्रभावित है।

मध्य प्रदेश के सिंगरौली स्थित नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड मुख्यालय में बच्चों के लिए विकसित पार्क

झारखंड में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के मुनिडीह क्षेत्र में कोल बेड मिथेन (सीबीएम) प्रोजेक्ट

vii. धमीरबरनी नदी के विभिन्न स्थानों में गाद निकालना, तालाबों को गहरा करना और जंगल, सीमाई करुवेलम को हटाना।

viii. एनएलसीआईएल अस्पताल, नेयवेली में आसपास के गांवों के आम निवासियों और मरीजों के लिए ओपी उपचार जैसे स्वास्थ्य देखभाल पहलों को बढ़ावा देना, परिधीय गांवों में रक्तदान शिविर आयोजित करना।

ix. बेटी बचाओ योजना के तहत नवजात शिशुओं को बेबी किट का बितरण।

x. जिला कुड्डालोर, तमिलनाडु के पीएचसी और सरकारी अस्पतालों में कंपाउंड दीवारों, सेप्टिक टैंक, शौचालय ब्लॉक, रोगी प्रतीक्षा कक्षों का निर्माण डीजल जेनरेटर सेट और अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना।

xi. चिदंबरम में चक्रवात निवार और ब्यूरेवी से प्रभावित जरूरतमंद परिवारों को 50 टन चावल का वितरण।

xii. जिला कुड्डालोर, तमिलनाडु के पीएचसी और सरकारी अस्पतालों में कंपाउंड दीवारों, सेप्टिक टैंक, शोचालय ब्लॉक, रोगी प्रतीक्षा कक्षों का निर्माण और डीजल जेनरेटर सेट और अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना।

xiii. नारिकुडी गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में आम जनता के उपयोग के लिए एम्बुलेंस प्रदान करना।

xiv. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए कोविड 19 टीकाकरण कोल्ड चेन उपकरणों की खरीद।

xv. तमिलनाडु में जिला कुड्डालोर में विभिन्न गांवों, प्राथमिक स्वास्थ्य केद्रों, स्कूलों आदि में आरसीसी ओएच टैंकों का निर्माण, बोरवेल उपलब्ध कराना और सबमर्सिबल पंपों की स्थापना।

xvi. विरुधुनगर और रामनाथपुरम आकांक्षी जिले के पेराइयूर गांव में सरकारी हायर सेकेंडरी स्कुल और मलयापट्टी गांव में प्राथमिक स्वास्थ केंद्र और सरकार को बोरवेल का निर्माण।

xvii. कुड्डालोर जिला, तमिलनाडु के स्कूलों में छात्रों के लाभ के लिए 14 इंसीनरेटर्स की स्वच्छता सेवाएं और स्थापना और कमीशर्निंग।

xviii. कुड्डालोर जिला, तमिलनाडु के सरकारी स्कुलों में रेस्ट रूम का निर्माण और आरओ शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना।

xix. विल्लुपुरम जिले के प्राथमिक यूनियन स्कूल (पीयूएमएस), वैरापुरम, ओलक्कुर ब्लॉक में शौचालयों का निर्माण, परिसर की दीवार, नया चरण, कक्षा कक्षों का नवीनीकरण और बोरवेल।

xx. जिला कुड्डालोर, तमिलनाडु के विभिन्न स्कूलों में पुस्तकालय निर्माण, अतिरिक्त कक्षा भवन, खेल के मैदानों का निर्माण, परिसर की दीबार, स्कूल के मैदान, शौचालय, खुले बहुउद्देशीय हॉल, स्मार्ट क्लास सेटअप क्लास रूम, कंपाउंड की दीवार का सुदृढ़ीकरण, विज्ञान शिक्षा के लिए स्कूल लैब उपकरण, उच्च जैसे बुनियादी ढांचे का निर्माण एनएलसी स्कूलों आदि में मास्ट लाइट, पब्लिक एड्रेस सिस्टम।

xxi. राजस्थान में ग्रामीण विकास के लिए सड़कें और सार्वजनिक प्रतीक्षालय जैसी बुनियादी सुविधाओं का निर्माण और प्रदान करना।

xxii. कुड्डालोर जिला, तमिलनाडु में ग्रामीण विकास के लिए निर्माण और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना, जैसे कि आरसीसी स्लैब पुलिया, सामुदायिक हॉल, गंगईकोंडन वार्ड नंबर II से माइन- II एप्रोच रोड, माइन-I।

xxiii. हुबली में आदिवासी कला और संस्कृति को बढ़ावा देना।

xxiv. कोविड-19 के लिए 'पीएम केयर्स फंड' में 20 करोड़ रू. का योगदान।

xxv. एसएचजी नेताओं के लिए विजन प्लानिंग अभ्यास पर कार्यशाला का आयोजन।

असम स्थित नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स में अधिभार डंप पर पौधारोपण

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के उत्तर प्रदेश स्थित ककरी क्षेत्र में रोपवे के जरिये कोयला परिवहन

xxvi. कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित करने के लिए डिजिटल कैमरा खरीदने के लिए वित्तीय सहायता।

xxvii. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पोलाथुर में खेल के बुनियादी ढांचे का विकास।

xxviii. झीलों की गाद निकाल कर जल संसाधन का संवर्धन।

xxix. राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण।

xxx. सशस्त्र बलों का कल्याण।

xxxi. जनप्रवेश – नेयवेली टीएस की सामाजिक सुविधाओं को परिधीय गांवों तक सस्ती पहुंच प्रदान करना और एनएलसी बस सेवा द्वारा सेवाओं को जोड़ना।

xxxii. विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए खेलकूद कार्यक्रमों का आयोजन, खेल सामग्री आदि उपलब्ध कराना।

xxxiii. आकांक्षी जे रामनाथपुरम के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण।

a. सरकारी हाई स्कूल, एलानचेम्बुर विलेज के लिए कक्षा भवन का निर्माण।

b. कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना के लिए प्रिंटर और स्कैनर वाले कंप्यूटर।

xxxiv. आकांक्षी जिले विरुधुनगर के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण।

a. सरकारी हाई स्कूल, के. चेट्टीकुलम गांव के लिए परिसर की दीवार।

b. थुमुचिन्नमपट्टी गांव में सरकारी हायर सेकेंड्री स्कूल के लिए कक्षा भवन।

c. सरकारी हाई स्कूल, उलीथमदई गांव में फर्श, दीवारों आदि के लिए कुछ सुधार कार्य।

d. सरकारी हायर सेकेंड्री स्कुल स्कूल, रेड्डीपट्टी विलेज के लिए छत के साथ डायस के निर्माण सहित पेवर ब्लॉक के साथ फ़र्श।

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के उत्तर प्रदेश स्थित खड़िया क्षेत्र में इंटिग्रेटेड वॉटर सप्लाई सिस्टम

xxxv. तमिलनाडु जिला कुड्डालोर के विभिन्न स्कूलों से एनएलसी स्कूलों आदि में पुस्तकालय भवन, अतिरिक्त कक्षा भवन, खेल के मैदानों का निर्माण, कंपाउंड की दीवार, स्कूल के मैदान, शौचालय, खुले बहुउद्देशीय हॉल, स्मार्ट क्लास सेटअप क्लास रूम, कंपाउंड की दीवार का सुदृढ़ीकरण, विज्ञान शिक्षा के लिए स्कुल लेब उपकरण, उच्च जैसे बुनियादी ढांचे का निर्माण और मास्ट लाइट, पब्लिक एड्रेस सिस्टम प्रदान करना।

xxxvi. एनएलसीआईएल अस्पताल, नेयवेली में आसपास के गांवों के आम निवासियों और मरीजों के लिए ओपी उपचार जैसे स्वास्थ्य देखभाल पहलों को बढ़वा देना, परिधीय गांवों में रक्तदान शिविर आयोजित करना।

xxxvii. ठेका श्रमिकों के बच्चों को शैक्षिक सहायता में योगदान।

xxxviii. विरुधुनगर और रामनाथपुरम के आकांक्षी जिले में ग्यारह सरकारी स्कूलों में मिनी साइंस सेंटर की स्थापना।

xxxix. मंदिरों को बैटरी से चलने वाली कार उपलब्ध कराना।

xl. राजस्थआन में ग्रामीण विकास के लिए सड़कें और सार्वजनिक प्रतीक्षालय जैसी बुनियादी सुविधाओं का निर्माण और प्रदान करना

xli. पीएवी के स्कूलों को 8 कंप्यूटर प्रदान करना।

xlii. अश्वरमऊ जल निकाय के जलाशयों का नवीनीकरण

xliii. एम्बुलेंस और मोबाइल हेल्थकेयर

xliv. यूपी के मिर्जापुर में 5 आरओ प्लांट की स्थापना

xlv. बांध व धारछुआ में ओवरहेड वाटर टंकियों के लिए जल वितरण पाइपलाइन की स्थापना

xlvi. पीएवी में 80 हैंडपंपों की स्थापना

xlvii. सजेती, कानपुर उत्तर प्रदेश में वॉशरूम का निर्माण और संबंधित मरम्मत

xlviii. 2 प्राइमरी स्कूल, 7 मिडिल स्कूल और 1 हाई स्कूल का नवीनीकरण

xlix. सभी सामान के साथ 180 एएच सौर बैटरी प्रणाली के साथ 1000 वीए सौर इन्वर्टर के साथ 500 डब्ल्यूपी के 8 सौर पैनलों की स्थापना

क. कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के तहत एक 'महारत्न' कंपनी है। सीआईएस दुनिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है और 259016 (1अप्रेल, 2021 की स्थिति के अनुसार) की श्रमशक्ति के साथ सबसे बड़े कॉर्पोरेट नियोक्ताओं में से एक है। सीआईएल भारत के आट (8) प्रांतीय राज्यों में फैले 85 खनन क्षेत्रों के माध्यम से संचालित होता है। कोल इंडिया लिमिटेड की 345 खानें (1 अप्रेल, 2021 की स्थिति के अनुसार) हैं, जिनमें से 151 भूमिगत, 172 ओपनकास्ट खानेंऔर 22 मिश्रित खानें हैं। सीआईएल की आट पूर्ण स्वामित्व वाली भारतीय सहायक कंपनियां हैं-ईसिएल, बीसीसीएल, सीसीएल, डब्ल्यूसीएल, एनसीएल, एसईसीएल, एमसीएल, और सीएमपीडीआईएल। इसके अलावा, सीआईएल की मोजाम्बिक में एक विदेशी सहायक कंपनी है, जिसका नाम कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटाडा (सीआईएल) है। सीआईएल ने गैर-पारंपारिक/स्वच्छ और नबीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए दो नई सहायक कंपनियों यानी सीआईएल नवीकरणीय ऊर्जा लिमिटेड और सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल के विकास के लिए सीआईएल सोलर पीवी लिमिटेड को शामिल किया है।

ख. कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) देश के कोयला उत्पादन में सबसे आगे है। सीआईएल अकेले देश के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 83 प्रतिशत उत्पादन करती है। सीआईएल अपने उत्पादन और आपूर्ति को अनिवार्य स्तर तक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे देश में जहां कुल विद्युत उत्पादन का 69% कोयला आधारित है, सीआईएल बस्तुत: देश के विद्युत क्षेत्र को सशक्त बनाता है। सीआईएल की कुल आपूर्ति का लगभग 80% विद्युत क्षेत्र को पूरा किया जाता है। सीआईएल सरकार के सरकारी राजकोष में-केन्द्र और राज्य दोनों-सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है और देश के सामाजिक ताने-बाने में एक से अधिक तरीकों से देशवासीयों के जीवन को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

ओडिशा के संबलपुर में महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड मुख्यालय में स्थापित सोलर पावर प्लांट

सीआईएल की उपलब्धियां एक नजर में

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2013-14	वित्तीय वर्ष 2014-15	वित्तीय वर्ष 2015-16	वित्तीय वर्ष 2016-17	वित्तीय वर्ष 2017-18	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वष 2021-22*
कोयला (मि.ट.)	462.42	494.24	538.75	554.14	567.36	606.89	602.14	596.00	622.6
ऑफ-टेक (मि.ट.)	471.58	489.38	534.50	543.32	580.28	608.14	581.93	574.48	661.9
ओबी हटाना (एम.क्यूब)	806.54	886.53	1148.91	1156.37	1178.11	1161.99	1154.33	1344.68	1366.05
कैपेक्स व्यय (करोड़ रुपये)	4329.86	5173.49	6123.03	7700.06	9334.55	7311.46	6269.65	13283.83	14833.71
सीएसआर व्यय (करोड़ रुपये)	409.37	298.10	1076.07	489.67	483.78	416.47	587.84	553.85	507

** आंकडे अंतिम हैं*

आठ वर्षों की उपलब्धियों का सारांश

वित्तिय वर्ष 2013-14 :	सीआईएल ने 290% की दर से अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है अर्थात अंकित मूल्य रु.10/- का रु. 29/- प्रति शेयर। यह कंपनी द्वारा दिया गया अब तक का सबसे अधिक लाभांश है।
वित्तीय बर्ष 2014-15 :	कोयले का उत्पादन 494.24 मिलियन टन था। 32 मिलियन टन की वृद्धि पिछले चार वित्तीय वर्षों के दौरान संयुक्त रूप रूप से प्राप्त वृद्धिशील वृद्धि से अधिक हौ। सीआईएल द्वारा भारत सरकार को 2014-15 में भुगतान किया गया कॉर्पोरेट टैक्स, भारतीय कॉरर्पोरेट क्षेत्र में सबसे अधिक नगद भुगतानों में से एक है।
वित्तीय बर्ष 2015-16 :	सीआईएल ने पहली बार 1,08,150.03 करोड़ रुपये की सकल बिक्री की रिकॉर्डिंग के साथ सकल बिक्री में 1 लाख करोड़ रुपये के जादुई आंकड़े को पार किया। पहली बार कोल इंडिया का उत्पादन और उठाव आधा बिलियन टन से अधिक हो गया है।
वित्तीय बर्ष 2016-17 :	2016-17 के दौरान सीआईएल ने 554.14 मिलियन टन (मि.ट.) का कोयला उत्पादन हासिल किया। कोयला उत्पादन ने 2012-13 में दर्ज किए गए 452.21एमटि के स्तर से वर्तमान स्तर तक पांच साल की अवधि में 100 मिलियन टन से अधिक की मात्रा में वृद्धि हासिल किया। वृद्धि का यह पैमाना 5 वर्षों के दौरान पहले कभी हासिल नहीं किया गया था। सिआईएल को 27 अक्टूबर 2016 को आईएस/आईएसओ 9001:2015 (गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली) और आईएस/आईएसओ 50001:2011 (ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली) प्रमाणन से मान्यता प्राप्त हुआ।
वित्तीय बर्ष 2017-18 :	पिछले वर्ष की तुलना में 6.8% की वृद्धि के साथ 580.28 मिलियन टन का अब तक का उच्च उठाव। वास्तव में, कोयले का उठाब 12.9 एमटी के मार्जिन के साथ उत्पादन को पार कर गई। विद्युत क्षेत्र को 454.24 मिलियन टन कोयले की आपूर्ति की गई, जो विद्युत संयंत्रों के लिए सबसे अधिक उठाव था, पिछले वर्ष की 425.4 मिलियन टन की उपलब्धि की तुलना में फिर से 6.8% वृद्धि हुई।
वित्तीय बर्ष 2018-19 :	पहली बार सीआईएल ने कोयला उत्पादन और उठाव में 600 मिलियन टन का आंकड़ा पार किया था। सीआईएल ने कुल मिलाकर अब तक की सर्वाधिक 1,40,603 करोड़ रुपये की सकल बिक्री और 92,896.08 करोड़ रुपये की शुद्ध बिक्री दर्ज की थी।
वित्तीय बर्ष 2019-20 :	मार्च, 2020 के दौरान 84.38 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया, कंपनी ने अपनी स्थापना के बाद से एक महीने में अब तक के सबसे अधिक उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया। 62.035 एमटिवाई की वृद्धिशील क्षमता वाली 31 खनन परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी (ईसी), **2011-12 के बाद से सबसे अधिक** पाप्त किया। 1,248.86 हेक्टेयर की 5 परियोजनाओं के लिए चरण II के एफसी को अनुमोदित किया गया था। FC का स्टेज।। **2014-15 के बाद सबसे ज्यादा है**।
वित्तीय बर्ष 2020-21 :	2020-21 के दौरान ओबीआर वॉल्यूम के लिहाज से अब तक का सबसे ज्यादा (1344.68 एमसीयूएम) था और एक दशक में ग्रोथ प्रतिशत के लिहाज से दूसरा सबसे ज्यादा (16.49) था। सीआईएल ने वित्त वर्ष 2011में पांच ई-नीलामी खिड़कियों के तहत 124 एमटी कोयला बुक किया है, **जो एक सर्वकालिक उच्च रिकॉर्ड बना**।
वित्तीय बर्ष 2021-22 :	622.6 मिलियन टन (मि.ट.) का सर्वकालीक रिकॉर्ड उच्च कोयला उत्पादन और 661.9 मिलियन टन का कोयला उठाव। समवर्ती रूप से, ओवरबर्डन निष्कासन बढ़कर 1,336 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीयूएम) हो गया, जो अब तक का एक और उच्च स्तर है। विद्युत मंत्रालय और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अनुमानित 99% मांग को पूरा करने के लिए विद्युत क्षेत्र में कोयला प्रेषण 540.4 मिलियन टन के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर था।

कोल इंडिया लिमिटेड संक्षिप्त वर्षवार उपलब्धियां

वित्तिय वर्ष	प्रमुख उपलब्धियां
	• वर्ष 2013-14 के लिये, कंपनी ने पिछले वर्ष की तुलना में क्रमश: 2.26%, 8.01% और 1.38% की बृद्धि के साथ 462.42 मिलियन टन का उत्पादन, 806.544 एमएम 3 के ओबी का हटाव और 471.58 मिलियन टन का उठाव हासिल किया है।
	• ईसीएल और बीसीसीएल ने न केवल कोयला उत्पादन, ओबी हठाने और उठाव के अपने एएपी लक्ष्यों को हासिल किया, बल्कि कोयला उत्पादन और औबि हठाने में भी उेल्लखनीय वृद्धि दर्ज की। एसईसीएल ने 5.11% की वृद्धि के साथ कोयला उत्पादन के एएपी लक्ष्य को भी हासिल कर लिया।
	• ओबी निष्कासन उल्लेखनीय था क्योंकि इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 8.01% की समग्र वृद्धि दर्ज की गई। सीाईएल में समग्र उत्खनन (कोयला + ओबी) में पिछले वर्ष की तुलना में 6.7% की वृद्धि दर्ज की गई।
	• विद्युत उपयोगिताओं को कोयले की आपूर्ति 353.83 मिलियन टन थी, जो लक्ष्य का 94.1% है और पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। यह प्रेषण उपलब्धि विद्युत उपयोगिताओं को एफएसए/एमओयू के तहत प्रतिबद्ध मात्रा के मुकाबले 86 फीरदी है।
	• 2013-14 दौरान कुल पूंजीगत व्यय 4329.86 करोड़ रूपये था।
वित्तिय वर्ष 2013-14	• सीआईएल ने 290% की दर से अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है अर्थात अंकित मूल्य रु. 10/- का पर 29/- प्रति शेयर। यह कंपनी द्वारा दिया गया अब तक का सबसे अधिक लभांश है। सीआईएल को मीडिया में '**द ज्वेल इन द गवर्नमेंट पीएसयू क्राउन**', एक नगद समृद्ध कंपनी, जो 'सरकारी बचाव के लिए आती है' और 'सरकारी खजाने को बड़ावा देने के लिए कोल इंडिया का विशेष लाभांश भुगतान्न के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। यह सीआईएल द्वारा 2013-14 के लिए उच्चतम अंतरिम लाभांश घोषित करने के संदर्भ में कहा गया था।
	• सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों ने रॉयल्टी, सेस, सेल्स टैक्स और अन्य लेवी के लिए 19713.52 करोड़ रुपये का भुगतान/समायोजन किया।
	• सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों ने साल के दौरान कुल कर-पूर्व लाभ रू. 22,879.54 करोड़ और कर पश्चात लाभ रू 15,111.67 करोड़ का भुगतान किया।
	• सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों ने साल के दौरान कुल कर-पूर्व लाभ रू. 22,879.54 करोड़ और कर पश्चात लाभ रू 15,111.67 करोड़ का भुगतान किया।
	• पारदर्शिता में सुधार के लिए सीआईएल ने मौजूदा 'संयुक्त नमूनाकरण और विश्लेषण' प्रणाली के स्थान पर 'थर्ड पार्टी' नमूनाकरण और विश्लेषण प्रणाली शुरु की।
	• सीआईएल एफएसए के तहत अपने विद्युत उपभोक्ताओं के लिए ''जैसा है-जहां है'' के आधार पर कोयले की आपूर्ति के लिए एक योजना लेकर आया है।
	• 2013-14 के दौरान, सीएसआर व्यय 409.37 करोड़ रूपये।
	• सीआईएल बोर्ड द्वारा 3 खनन परियोजनाओं और 4 खनन परियोजनाओं को मंज़ूरी दी गई है।

वित्तीय वर्ष	प्रमुख उपलब्धियां
वित्तीय वर्ष 2013-14	• पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 923.73 हेक्टेयर क्षेत्र से जुड़े 11 वानिकी प्रस्तावों के लिए चरण ।। मंजूरी और 71.54 एमटीवाई की क्षमता के 48 पर्यावरण निकासी प्रस्तावों को मंजूरी दी गइ
	• 2013-14 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों ने वृक्षारोपण /वनरोपण कार्यक्रम के तहत 526 हेक्टेयर में 13.36 लाख पौधे लगाए हैं।
वित्तीय वर्ष 2014-15	• कोयले का उत्पादन 6.88% की वृद्धि के साथ 494.24 मिलियन टन था। 32 मिलियन टन की वृद्धि पिछले चार वित्तीय वर्षों के दौरान संयुक्त रूप से प्राप्त वृद्धिशील वृद्धि से अधिक है।
	• कोल इंडिया OB के 886.53 एमएम3 को हटाया और विगत तीन वर्षों की तुलना में क्रमश: 6.88%, 9.92% और 3.77% की वृद्धि के साथ 489.38 मिलियन टन ऑफ-टेक प्राप्त किया।
	• देश की विद्युत उपयोगिताओं को प्रेषण ने 8.9% की स्वस्थ वृद्धि दर्ज की। कोयले की आपूर्ति वित्त वर्ष 2014 की तुलना में 31.57 मिलियन टन बढ़कर 385.40 मिलियन टन हो गया।
	• गैर-रेल मोड से कुल प्रेषण लक्ष्य का लगभग 101 प्रतिशत रहा। रेल मोड के माध्यम से प्रेषण में वृद्धि 2.7% थी जबकि समग्र गैर-रेल मोड में इसमें 5.4% की वृद्धि हुई। सड़क प्रेषण में पिछले वर्ष की तुलना में 8.2% की वृद्धि हुई। एमजीआर का मूवमेंट पिछले साल से 1.5 फीसदी ज्यादा था।
	• सभी सहायक कंपनियाँ पिछले साल की तुलना में उत्पादन में वृद्धि में हासिल किया। 2014-15 के दौरान ओबी निष्कासन में अद्भूत वृद्धि हुआ। एमसीएल के अलावा, सभी अन्य सहायक कंपनियों ने ओबी निष्कासन में वृद्धि हासिल किये। भूमि अधिग्रहण की समस्या के कारण एमसीएल में नकारत्मक वृद्धि हुई। बीसीसीएल के अलावा अन्य सभी सहायक कंपनियों ने पिछले साल की तुलना में ऑफ-टेक में वृद्धि हासिल की। कम वैगन आपूर्ति BCCL में नकारात्मक वृद्धि का कारण था।
	• वर्ष के दौरान कुल पूंजीगत व्यय 5173.49 करोड़ रुपये था।
	• ईसीएल बीआईएफआर से बाहर आया। बीसीसीएल को मिला **मिनी रत्न दर्जा**।
	• **भारत सरकार ने जनवरी 2015 में सीआईएल में अपनी हिस्सेदारी का 10 और बेच दिया। 22,557 करोड़ रुपये की राशि वसूल की गई। यह किसी भी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचकर भारत सरकार को प्राप्त सबसे अधिक विनिवेश राशि थी।**
	• कोल इंडिया ने कुल मिलाकर 21,583.92 करोड़ रुपए का कर-पूर्व लाभ और 13,726.70 करोड़ रूपये का कर पश्चात लाभ अर्जित किया।
	• कोल इंडिया ने भारत सरकार को 9,572.05 करोड़ रुपये के कॉर्पोरेट टैक्स का भुगतान किया, जो भारतीय कॉपोरेट क्षेत्र में सबसे अधिक नकद भुगतान में से एक है।
	• सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों ने 21,482.21 करोड़ रुपये रॉयल्टी, से, सेल्स टैक्स और अन्य लेवी का भुगतान / समायोजित किया।
	• 73.42 मिलियन टन की वार्षिक क्षमता और कुल 7951.17 करोड़ रुपए का पुंजी निवेश के साथ सीआईएल बोर्ड ने 7 कोयला परियोजनाओं की मंजुरी दी थी।
	• एमसीएल अर्थात महानदी बेसिन पावर लिमिटेड में सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट (2×800 मे.वा.) की स्थापना के लिए परियोजना रिपोर्ट को सीआईएल वोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था।

वित्तीय वर्ष	प्रमुख उपलब्धियां
वित्तीय वर्ष 2014-15	• एमओईएफ से 107.36 एमटी क्षमता के लिए 38 पर्यावरण मंजुरी प्राप्त की गई थी।
	• सीआईएल ने 15.74 लाख पौधा लगाकर लगभग 82 मिलियन पौधों की हरित संपदा बनाई।
	• 414 प्रबंधन प्रशिक्षुओं को खुले विज्ञापन के माध्यम से विभिन्न विषयों में भर्ती और सामिल किया गया है। कैंपस भर्ता के माध्यम से 264 प्रबंधन प्रशिक्षुओं की भर्ती की गई और कंपनी में सामिल हो गए।
	सीआईएलने १९२ सीनियर मेडिकल ऑफिसर की भी भर्ती की।
	• **सीएसआर – कोल इंडिया और इसकी सहायक कंपनियों ने सीएसआर पहल पर वित्त वर्ष 2015 में 298.10 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। कुछ प्रमुख पहलें प्रकार हैं:**
	➢ 30,340 विद्यालयों में 48,735 शौचालयों के निर्माण के माध्यम से स्वच्छ विद्यालय अभियान।
	➢ टाटा मेडिकल सेंटर (टीएमसी) के साथ प्रेमाश्रय के निर्माण के लिए 41.11 करोड़ रुपये मंजुत किए हैं, जो दश मंजिला इमारत है, जो इलाज के लिए टीएमसी में आने वाले आर्थिक रुप से कमजोर बाहरी रोजियों के लिए आवास की सुविधा प्रदान करती है।
	➢ पश्चिम बंगाल के पिछड़े जिले पुरुलिया के 40 गांवों में विकाश कार्यों के निष्पादन के लिए 32.92 करेड़ रुपये की परियोजना लागत पर ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टीईआरआई) के साथ समझौता ज्ञापन।
	➢ पश्चिम बंगाल के कल्याणी में एक भारतीय सुचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) की स्थापना, पीपीपी मॉडल पर औद्योगिक भागीदारों में से एक के रुप में, परियोजना के लिए 6.40 करोड़ रुपये का योगदान।
	➢ **कोल इंडिया ने भी दिया फंड –** ■ अलीपुरद्वार नगर पालिका, पश्चिम बंगाल के वंचित लोगों के लिए 78.40 लाख रुपये की लागत से जल उपचार संयंत्र की स्थापना के लिए अलीपुरद्वार नगरपालिका को।
	■ रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम, मुजफ्फरपुर, बिहार में 4.93 करोड़ रुपये की लागत से 100 बोड से युक्त चैरिटेबज आंख ई एंड टी, दंत चिकित्सा निदान केंन्द्र का निर्माण।
	■ ग्रामीण आबादी में, जहां साक्षरता कम है जागरुकता कार्यक्रमी के माध्यम से प्रचार और निवारक स्वास्थ देखभाल के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लार्जर अवेयरनेस (एनआईएलए), असम को, जिसकी लागत 31.51 लाख रुपये है।
	■ नेशनल चैरिटेबल सोसाइटी, प्रतापगड़, यूपी में 50 सौर ऊर्जा संचालित स्ट्रीट लाइट और 50 हैंड पंपों की स्थापना के लिए 30.45 लाख रुपये की लागत।
	■ सुनेबेड़ा क्षेत्र विकाश एर्जेसी (एसएडीए), ओडिशा ने 12000 परिवारों को 3.60 करोड़ रुपये की लागत से साइकिल उपलब्ध कराना।
	• **उपभोक्ता संतुष्टि :** ➢ सीआईएल ने लगभग 296 एमटी प्रति वर्ष की क्षमता के लिए कोयला प्रबंधन संयंत्रों का निर्माण किया है ताकि अपने उपभोक्ताओं को कुचल/आकार के कोयले के प्रेषण को अधिकतम किया जा सके।

वित्तीय वर्ष	प्रमुख उपलब्धियां
वित्तीय वर्ष 2014-15	सीआईएल ने 112.6 एमटीवाई की संयुक्त क्षमता के साथ 15 और कोयला वाशरी स्थापित करने की कार्रवाई भी शुरु की है।
	➢ शेल/पत्थर को चुनना, पारंपरिक तरीके से और साथ ही सतही खनिकों द्वारा चयनात्मक खनन, संभावना को कम करने लिए उचित ब्लास्टिंग प्रक्रिया/तकनीक अपनाना जैसे इपाय।
	➢ उपभोक्ता संतुष्टि सुनिश्चित करने और उपभोक्ता शिकायतों के समाधान के लिए गुणवत्ता प्रबंधन और उपभोक्ता शिकायतों के निवारण पर विशेश जोर दिया गया है। निपटाई गई शिकायतों का प्रतिशत 99.44% या [अप्रैल 2014 से मार्च 2015]।
वित्तीय वर्ष 2015-16	• 9.01% वर्ष-दर-वर्ष की वृद्धि के साथ कंपनी ने 538.75 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया। **यह पहली बार है जब सीआईएल ने 0.5 बिलियन टन कोयला उत्पादन किया है। माननीय प्रधान मंत्री ने 13 फरवरी 2016 को मुंबई में 'मेक इन इंडिया' के उपने उद्घाटन भाषण में टिप्पणी की कि "इस वर्ष हम अब तक का सबसे अधिक कोयला उत्पादन रिकॉर्ड करेंगे" जी सच हो गया था।**
	• कंपनी ने 534.50 एमटी का ऑफ-टेक शामिल किया। पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 9.23% की वृद्धि के साथ। **यह पहली बार है जब सीआईएल ने 0.5 अरब टन कोयला प्रेषण को पार किया है।** विद्युत संयंत्रों की कोयले आवश्यकता को पूरा करने के लिए एमओसी द्वारा विशेष फॉरवर्ड ई-नीलामी योजना शुरू की गई थी। गैर-विद्युत क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए भी इसी तरह की एक योजना विशेष ई-नीलामी के रूप में शुरू की गई थी।
	• सीआईएल ने ओबीआर में 1031 मिलियन क्यूबिक मीटर के लक्ष्य को पार कर लिया था, जो 24 फरवरी 2016 को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक महीने से अधिक समय पहले ही 1148.908 मिलियन क्यूबिक मीटर का वास्तविक लक्ष्य हासिल कर लिया था, जो लक्ष्य संतुष्टि का 111% है।
	• **पहली बार, सीआईएल ने 108150.03 करोड़ रुपये की सकल बिक्री हासिल की है, एक ऐतिहासिक उपलब्धि।**
	• कोयले की कमी कारण एक भी विद्युत-उपयोगिता गंभीर या अति-गंभीर स्तिति में नहीं थी। • **कोयले की बेहतर प्रेषण और बहतर गुणवत्ता के कारण, 2015-16 के दौरान भारत में कोयले का आयात कम हो गया था।**
	• कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी वेस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड ने पर्यावरण के अनुकूल खान पर्यटन शुरू किया जो अत्यधिक लोकप्रिय था। भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने 27 मार्च 2016 को प्रसारित अपने "मन की बात" कार्यक्रम में इसका विशेष उल्लेख किया।
	• 2015-16 के दौरान समग्र पूंजीगत व्यय 6,123.03 करोड़ रुपये।
	• 2015-16 में सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों ने कुल 21,589.09 करोड़ रुपये कर-पूर्व लाभ, 14,274.33 करोड़ रुपये कर पश्चात लाभ (0.04 करोड़ रुपये के थोड़ा शेयर हानि छोड़कर, पिछले वर्ष: 0.09 करोड़ रुपये)।

वित्तीय वर्ष	प्रमुख उपलब्धियां
वित्तीय वर्ष 2015-16	• कोल इंडिया ने वित्त वर्ष-2016 में भारत सरकार को 7,012.35 करोड़ रुपये का कॉर्पोरेट टैक्स चुकाया। • कोल इंडिया और इसकी सहायक कंपनियों ने 29,084.11 करोड़ रुपये का रॉयल्टी, उपकर, वैट और अन्य लेवी का भुगतान-समायोजन किया है। सीआईएल ने 27.40 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम लाभांश का भी भुगतान किया। • पुरुषों और सामग्री के परवहन के लिए ईसीएल की झंझरा खान में पहली बार डीजल संचालित फ्री व्हीकल (एफएसवी) पेश किया गया है। • वित्त वर्ष 2016 के दौरान लघु और मध्यम क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लाभ के उद्देश्य से एक वेब पोर्टल (कोयला आवंटन और निगरानी प्रणाली) शुरू की। वेब पोर्टल राज्य नामित एजेंसियों (एसएनए) द्वारा कोयले के वितरण के लिए है, जो छोटे और मध्यम उपभोक्ताओं को सार्वजनिक डोमेन में एसएनए, उपलब्धता, कोयले की बुकिंग-आपूर्ति वितरण के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। • कोल इंडिया ने मार्च 2016 तक 36,896.26 हेक्टेयर से अधक क्षेत्र को कवर करते हुए लगभग 92.35 मिलियन पेड़ों की हरित संपदा बनाई है। इसमें से वित्तीय वर्ष 2016 में 719 हैक्टेयर (हेक्टेयर) में 1.68 मिलियन पेड़ लगाए गए हैं। 50 प्रमुख औसीपी की में पुनर्वास गतिविधियों की निगरानी के लिए उपग्रह निगरानी को अपनाया गया है। • सीआईएल बोर्ड द्वारा 159.25 मिलियन टन की अंतिम क्षमता और 26480.74 करोड़ रुपये कुल पूंजी निवेश के साथ 9 कोयला खनन परियोजनाओं और 3055.15 करोड़ रुपये के कुल पूंजी निवेश के साथ एक गैर खनन परियोजना को मंजूरी दी गई है। • कोल इंडिया में 100 करोड़ पुरये से अधिक की लागत वाली कोयला खनन परियोजनाओं की वेब आधारित ऑनलाइन निगरानी की शुरुआत की गई है। • 2015-16 के दौरान कोल इंडिया की विभिन्न अनुषंगियों में 5,378.98 हेक्टेयपर भूमि का कब्जा लिया गया है। • **कॉपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व :** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसरण में सीएसआर पर कुल व्यय 1076.07 करोड़ रुपये और आगे 6.00 करोड़ रुपये नेपाल भूकंप राहत कोष में दान के रूप में कुल मिलाकर 1082.07 करोड़ रुपये थे। कुछ प्रमुख पहलें इस प्कार हैं: ➢ 53,412 शौचालयों का निर्माण कर स्वच्छ विद्यालय अभियान की दिशा में पहल। इन शौचालयों के निर्माण पर 31 मार्च, 2016 तक कुल 820.44 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। ➢ 1.14 करोड़ रुपये की लागत से कोलकाता में जलीय खेल छात्रावास का निर्माण। ➢ यातायात विभाग, कोलकाता पुलिस द्वारा स्कूली बच्चों के बीच सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 69.85 लाख रुपये। ➢ पश्चिम बंगाल हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, कोलकाता ने 5 करोड़ रुपये की लागत से 3 इलेक्ट्रिक बसें और 1 छोटा इलेक्ट्रिक सर्विस मेंटेनेंस व्हीकल खरीदा है। ➢ स्कूल शिक्षा विभाग, पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले, उत्तर 24 परगना और नदिया जिले पश्चिम बंगाल में छात्राओं को 9,000 साइकिलें प्रदान करने के लिए 2.88 करोड़ रुपये।

वित्तीय वर्ष	प्रमुख उपलब्धियां
वित्तीय वर्ष 2015-16	• सीआईएल को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेल को बढ़ावा देने के लिए 'राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार-2015' से सम्मानित किया गया।
	• इंडिया टुडे पीएसयू अवार्ड्स इवेंट में सीआईएल को 'फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी' अवार्ड से सम्मानित किया गया।
	• सीआईएल को ब्यूरोक्रेसी टुडे के 'बीटी-स्टार एक्सीलेंस अवार्डस 2015' द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उत्कृष्टता से सम्मानित किया गया।
	• कोल इंडिया ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टीओएलआईसी) (पीएसयू) द्वारा संघ की राजभाषा नीति के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया।
	• सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों में ऊर्जा दक्षता प्रावधानों को बढ़ावा देने के लिए सीआईएल ने एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) के साख एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सीआईएल की पहल के परिणामस्वरूप एमसीएल, बुर्ला, सीएमपीडीआईएल, रांची और सीआईएल मुख्यालय कोलकाता में क्रमश: में 2.0 मेगावाट क्षमता, 0.19 मेगावाट क्षमता और 0.14 मेगावाट सौर पीवी विद्युत संयंत्रों की स्थापना हुई है;
	• वर्ष के दौरान, सीएमपीडीआई ने कुल 16 फॉर्म -I तैयार किए हैं और 34 ड्राफ्ट ईआईए/ईएमपी तैयार किए हैं। 23 पर्यावरण मंजूरी भी प्राप्त की गई थी।
	• कोल इंडिया ने विभागीय चयन/पदोन्नति प्रक्रिया के माध्यम से कार्यकारी संवर्ग में 281 चिकित्सा अधिकारियों, 448 प्रबंधन प्रशिक्षुओं, 44 गैर-कार्यकारी स्तर के कर्मचारियों की भर्ती की।
	• होटवार, रांची में मौजूदा विश्व स्तरीय स्टेडियम / बुनियादी ढांचे में पंद्रह खेल अकादमियों और खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए झारखंड सरकार और सीसीएल के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जहां राष्ट्रीय खेल 2011 का आयोजन किया गया था।
वित्तीय वर्ष 2016-17	• 2016-17 के दौरान कोल इंडिया ने 554.14 मिलियन टन (मि.ट.) का कोयला उत्पादन हासिल किया। कोयला उत्पादन ने 2012-13 में दर्ज किए गए 452.21 एमटी के स्तर से वर्तमान स्तर तक पांच साल की अवधि में 100 मीट्रिक टन से अधिक की मात्रा में वृद्धि की। वृद्धि का यह पैमाना 5 साल की अलधि के दौरान पहले कभी हासिल नहीं किया गया था। कुल ओबी निष्कासन 1156.37 एमसीयूएम था।
	• एनसीएल, सीसीएल और बीसीसीएल का प्रदर्शन विशिष्ट रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि तीनों कंपनियों ने बिषम परिस्थितियों में कोयला उत्पादन में अपने-अपने एएसी लक्ष्य हासिल किए। एसईसीएल वर्ष के दौरान 140 मिलियन टन के साथ कोयला उत्पादन के शीर्ष पर बना हुआ है, एमसीएल 139.21 मिलियन टन के साथ एक करीबी प्रतिस्पर्धी रन अप दे रहा है।
	• वित्त वर्ष 2017 के दौरान कच्चे कोयले की उठान 543.32 एमटी थी, जो साल दर साल तुलना में 8.82 एमटी की वृद्धि है। एनसीएल ने भारी मानसून के बावजूद उठान में भी एएपी का लक्ष्य हासिल किया। ईसीएल, सीसीएल, एनसीएल, एमसीएल और एनईसी ने पिछले वर्ष की तुलना में अधिक उठान हासिल किया।
	• वर्ष के दौरान विद्युत उपयोगिताओं (विशेष फॉरवर्ड ई-नीलामी सहित) को कोयला प्रेषण पिछले वर्ष (413.11 मिलियन टन) की तुलना में 3% की वृद्धि दर्ज करते हुए 425.397 मिलियन टन था। एनटीपीसी को प्रेषण में पिछले वर्ष की तुलना में 4.9% की वृद्धि दर्ज की गई, जो एफएएस/एमओयू प्रतिबद्धता के विरुद्ध 95% की भौतिकता दर्ज करता है।

वित्तीय वर्ष	प्रमुख उपलब्धियां
वित्तीय वर्ष 2016-17	• कोल इंडिया को 27 अक्टूबर, 2016 को आईएस/आईएसओ 9001:2015 (गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली) और आईएस/आईएसओ 50001:2011 (ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली) प्रमाणन प्राप्त हुआ।
	• 2016-17 के दौरान कुल पूंजीगत व्यय 7700.06 करोड़ रुपये था।
	• वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी का सकल बिक्री कारोबार 1,22,294.46 करोड़ रुपये था। कोल इंडिया ने कुल मिलाकर 14,433.71 करोड़ रुपये का कर-पूर्व लाभ और 9,265.98 करोड़ रुपये का कर पश्चात लाभ अर्जित किया।
	• कोल इंडिया ने वित्त वर्ष 2016-17 में भारत सरकार को 8,942.70 करोड़ रुपये कॉर्पोरेट करों का भुगतान किया। सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों ने भी 44,070.22 करोड़ रुपये की रॉयल्टी, उपकर, वैट, डीएमएफ और एनएमईटी और अन्य लेवी का भुगतान/समायोजन किया था। कंपनी ने 19.90 रुपये प्रति शेयर की दर से 12,352.76 करोड़ रुपये के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया था।
	• अगस्त 2016 में ईसीएल के झंझरा संयुक्त यूजी माइन (3.5 मिलियन टन) में लॉन्गवॉल तकनीक की शुरुआत के साथ भूमिगत उत्पादन को बड़ा बढ़ावा मिला।
	• 2016-17 के दौरान विभिन्न अनुषंगियों में कुल 3826.19 हेक्टेयर भूमि का कब्ज़ा लिया गया है।
	• वर्ष के दौरान सीआईएल की विभिन्न परियोजनाओं/खानों के समूह, वाशरीज और बालू खनन परियोजनाओं के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से 17 पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त की गई।
	• ओपनकास्ट खानों से कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए उच्च क्षमता वाले उपकरण, ऑपरेटर स्वतंत्र ट्रक डिस्पैच सिस्टम, जीपीएस / जीपीआरएस का उपयोग कर वाहन ट्रैकिंग सिस्टम, लेजर स्कैनर का उपयोग करके तेजी से लोडिंग और निगरानी के लिए सीएचपी और सिलोस की शुरूआत की योजना बनाई गई है।
	• बड़े पैमाने पर कंटीन्यूअस माइनर टेक्नोलॉजी की शुरुआत, चुनिंदा जगहों पर लॉन्ग वॉल टेक्नोलॉजी, प्रमुख खानों में मैन राइडिंग सिस्टम और टेली-निगरानी तकनीकों के उपयोग को भूमिगत खानों से उत्पादन बढ़ाने के लिए प्राथमिकता मिलती रही।
	• आंतरिक रूप से कोयले की गुणवत्ता की निगरानी के लिए, नमूने के पूरे जीवन चक्र को पकड़ने के लिए नियमित आधार पर कोयले की गुणवत्ता का विश्लेषण करने के लिए सीआईएल द्वारा एक पोर्टल तैयार किया गया था। अधिक उपभोक्ता संतुष्टि के लिए और उपभोक्ता शिकायतों को हल करने के लिए गुणवत्ता प्रबंधन का पालन किया जा रहा है। शिकायतों के निस्तारण के लिए ऑनलाइन फाइलिंग शुरू कर दी गई है। वर्ष के दौरान 99.42 प्रतिशत उपभोक्ता शिकायतों का समाधान किया गया।
	• भारत सरकार द्वारा की गई हरित पहल को बढ़ावा देने के लिए, सीआईएल ने 1000 मेगावाट सौर उर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए एमएनआरई को हरित ऊर्जा प्रतिबद्धता पत्र प्रस्तुत किया है। इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए, सीआईएल ने भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया हैं।
	• सीआईएल की सहायक कंपनियों ने 37557.458 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को कवर करते हुए लगभग 94.015 मिलियन पेड़ लगाए हैं। मार्च 2017 तक और 2016-17 के दौरान 661.20 हेक्टेयर क्षेत्र में 1.66 मिलियन पेड़ लगाए गए हैं।

वित्तीय वर्ष	प्रमुख उपलब्धियां
वित्तीय वर्ष 2016-17	• **कोल इंडिया ने रु. सीएसआर पहलों पर वित्त वर्ष 2017 के अंत में 489.67 करोड़ रुपये खर्च किये।** की गई प्रमुख गतिविधियाँ है:
	➢ युवा मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से 75 करोड़ रुपये (25 करोड़ रुपये प्रति वर्ष) के परियोजना परिव्यय पर भारत की ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों का प्रशिक्षण और तैयारी।
	➢ 65 करोड़ रुपये के परिव्यय से 10 शहरों में 16 सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों की स्थापना।
	• सीआईएल को निम्नलिखित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया:
	➢ 2017 में डन एंड ब्रैडस्ट्रीट द्वारा कोयला और कोयला उत्पाद।
	➢ 2017 में एबीपी न्यूज द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन।
	➢ 2016 में हिंदुस्तान पीएसयू अवाड्‌र्स द्वारा सर्वश्रेष्ठ महारत्न श्रेणी में दलाल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट जर्नल अवार्ड द्वारा सबसे कुशल और तेजी से बढ़ते महारत्न।
	➢ फाइनेंशियल एक्सप्रेस द्वारा सर्वश्रेष्ठ सीएफओ पुरस्कार।
	• उचित गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम सीसीओ द्वारा राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से 871 खानो/लोड़िंग पॉइंट्स/अंशों के ग्रेड का स्वतंत्र मूल्यांकन किया गया था।
	• सीआईएल ने कोयला प्रबंधन संयत्र की क्षमता को लगभग 320 एमटी प्रति वर्ष बढ़ाया ताकि विद्युत क्षेत्र को कुचल/आकार के कोयले के प्रेषणा को अधिकतम किया जा सके। सीआईएल पिट हेड को छोड़कर सभी विद्युत संयंत्रों की 01.01.2016 के प्रभाव से (-) 100 मिमी आकार के कोयले की आपूर्ति कर रहा है।
	• वर्ष 2016-2017 के दौरान 4 परियोजनाओं ने कोयला उत्पादन शुरू किया है। 56.25 मिलियन टन की अंतिम क्षमता और कुल 8931.05 करोड़ रुपये पूंजी निवेश के लिए 8 कोयला खनन परियोजनाएं सीआईएल बोर्ड द्वारा स्वीकृत किए गए।
	• सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों मे ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 08.02.2016 को सीआईएल और ईईएसएल (एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
	• 38 चिकित्सा विशेषज्ञ और चिकित्सा अधिकारी कंपनी में शामिल हुए। 438 प्रबंधन प्रशिक्षु जो परिसरों के माध्यम से चुने गए हैं, शामिल हो गए हैं। इसके अलावा, 175 गैर-कार्यापालक स्तर के कर्मचारियों को बिभागीय चयन/पदोन्नति प्रक्रिया के माध्यम से कार्यकारी संवर्ग में पदोन्नत किया गया।
वित्तीय वर्ष 2017-18	• पिछले वर्ष की तुलना में 6.8% की वृद्धि के साथ 580.28 मिलियन टन का सर्वकालिक उच्च उठान हासिल किया। वास्तव में, कोयले की उठान 12.9 एमटी के मार्जिन के साथ उत्पादन को पार कर गई थी। विद्युत क्षेत्र को 454.24 मिलियन टन कोयले की आपूर्ति की गई, जो विद्युत संयंत्रों के लिए सबसे अधिक उठान था, पिछले वर्ष की 425.4 मीट्रिक टन की उपलब्धी की तुलना में फिर से 6.8% वृद्धि थी।

वित्तीय वर्ष	प्रमुख उपलब्धियां
वित्तीय वर्ष 2017-18	• पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 567.36 मीट्रिक टन कोयले के उत्पादन में 13 मीट्रिक टन से अधिक की वृद्धि देखी गई, जिसमें 2.4% की वृद्धि दर्ज की गई थी। 1 अप्रैल 2018 को कोयले की सूची पिछले वर्ष के 68.42 मीट्रिक टन के मुकाबले 55.55 मीट्रिक टन थी, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 13 मीट्रिक टन का स्टॉक परिसमापन हुआ। कुल ओबी निष्कासन 1178.11 एमसीयूएम था।
	• लंबे समय से लंबित, दो प्रमुख रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, तोरी-बालूमठ खंड (सीसीएल के अधिकार क्षेत्र में तोरी-शिवपुर मंडल में) और झारसुगुडा-बरपाली-दरडेगा खंड (एमसीएल के अधिकार क्षेत्र के तहत) को चालू किया गया था, जो जमा आधार पर बनाए गए थे और अब चालू हैं।
	• दो कोकिंग कोल वाशरीज, 1.6 एमटीवाई की क्षमता वाली दहीबारी वाशरी और 5 एमटीवाई के साथ पाथेरडीह वाशरी चालू की गई।
	• एमसीएल में खड़िया 6 एमटीपीए सीएचपी/आरएलएस, एनसीएल और भरतपुर 15 एमटीपीए सीएचपी/आरएलएस में रैपिड लोडिंग सिस्टम के साथ दो नए कोल हैंडलिंग प्लांट चालू किए गए हैं।
	• 1524.27 करोड़ रुपये की स्वीकृत पूंजी के साथ 41.39 मिलियन टन की अंतिम क्षमता वाली 10 कोयला परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं।
	• 237.22 मीट्रिक टन कोयले के कुल ईसी के साथ 24 पर्यावरण मंजूरी प्राप्त की गई थी। उपरोक्त के अलावा, 1919.49 हेक्टेयर के क्षेत्र को कवर करने वाली 14 (चरण I) वन मंजूरी और 832.55 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने वाली 7 (चरण II) वन मंजूरी भी प्राप्त की गई थी।
	• देश भर में 3 लाख से अधिक श्रमिकों को प्रभावित करने वाले 10वें वेतन समझौते को 10 अक्टूबर 2017 को जेबीसीसीआई की 10वीं बैठक में अंतिम रूप दिया गया था, जिसमें सीआईएल प्रबंधन और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों दोनों के प्रतिनिधि शामिल थे।
	• कैलेंडर वर्ष 2017 में, 2016 की तुलना में सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों में मृत्यु दर में 33% और गंभीर चोटों में 9% की कमी आई थी।
	• कोल इंडिया ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारत सरकार को 7432.89 करोड़ रुपये कॉर्पोरेट करों का भुगतान किया। कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों ने थी 44,046.57 करोड़ रुपये का रॉयल्टी, जीएसटी, उपकर, डीएमएफ और एनएमईटी और अन्य लेवी का भुगतान/समायोजन किया था।
	• 2017-18 के दौरान, कोल इंडिया ने 10,726.44 करोड़ रुपये का कर-पूर्व लाभ और 7,020.22 करोड़ रूपये का कर पश्चात लाभ कमाया।
	• 16.50 रूपये प्रति शेयर की दर से 10,242.24 करोड़ रुपये के अंतरिम लाभांश का भी भुगतान किया गया है।
	• 2017-18 के दौरान कुल पूंजीगत व्यय 9334.55 करोड़ रुपये था।
	• इसीएल, बीसीसीएल सीसीएल और डब्ल्यूसीएल को मिलाकर 11 कोयला ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। ये नए ब्लॉक इन सहायक कंपनियों को निकट भविष्य में प्रति वर्ष 100 मिलियन टन से अधिक कोयले का उत्पादन करने में मदद करेंगे।
	• 24.60 मिलियन टन की क्षमता और 4155.46 करोड़ कुल पूंजी निबेश वाली 4 कोयला खनन परियोजनाएं सीआइएल बोर्ड द्वारा अनुमोदिन की गइे थी।

वित्तीय वर्ष	प्रमुख उपलब्धियां
	• झारसुगुड़ा-बरपल्ली-सरडेगा रेल लिंक (एसईसीआर) 05.04.2018 को चालू किया गया।
	• 2017-18 के दौरान सीआइएल की विभिन्न अनुषंगियों में 3687.61 हेक्टेयर भूमि का कब्जा लिया गया है।
	• सीआइएल ने सीएमपीडीआइ के सहयोग से हाल ही में सीआइएल में 20 करोड़ रुपये और उससे अधिक की लागत वाली चल रही परियोजनाओं की निगरानी के लिए एक पोर्टल एमडीएमएस (माहन डेटा बेस मैनजमेंट सिस्टम) लॉन्च किया।
	• नमूना के पूरे जीवन चक्र को पकड़ने के लिए सीआइएल द्वारा एक पोर्टल उत्तम (अनलॉकिंग ट्रांसपेरेंसी बाय थडे पार्टी असेसमेंट ऑफ माइन्ड कोल) शुरू किया गया है। पोर्टल की मदद से नियमित आधार पर कोयले की जानकारी कोल कंपनी और उपभोक्ताओं दोनों को मिल सकेगी।
	• 2018 को समाप्त वित्त बर्ष में **सीएसआर पहल** पर 483.78 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। **की गइे प्रमुख गतिबिधियों निम्नलिखित हैं:**
	➢ क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, टाटा मेडिकल सेंटर, कोलकाता, राजीव गांधी कैंसर संस्थान और अनुसंधान केन्द्र, नइे दिल्ली, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नइे दिल्ली और पोस्ट ग्रजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगड़ को प्रति रोगी 10लाख रुपये की वित्तीय सहायता के माध्यम से थेलेसीमिया रोगियों में बीमारी का इलाज और बेहतर प्रबंधन।
वित्तीय वर्ष 2017-18	➢ ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टीइेआरआइे) के माध्यम से पुरुलिया, पश्चिम बंगाल में विभिन्न विकास कार्य : ▪ घरों की ऊर्जा जरूरतों के लिए नवीकरणीय समाधानों की बढ़ावा देना-एकीकृत घरेलू ऊर्जा प्रणालियों और सौर लाइटों की स्थापना।
	▪ कृषि, हरित और क्षमता निर्माण पहल। स्वच्छता – 5,660 घरों में व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण।
	▪ 40 विद्यालयों में ज्ञान सह संसाधन केन्द्रों के माध्यम से शिक्षा।
	➢ मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का निर्माण – तालचर, औडिशा में एमसीएल द्वारा महानदी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च (एमआईएमएसआर)।
	➢ सीसीएल के लाल/सीसीएल की लाडली – सीसीएल के कमांड क्षेत्रों में रहने वाले पीएपी (परियोजना प्रभावित लोगों) के मेधावी छात्रों को 10 वीं और 12 वीं कक्षा के लिए आवास, बोर्डिंग और औपचारिक स्कूली शिक्षा के साथ विशेषज्ञों से कोचिंग प्रदान करके सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से एक पहल उन्हें आईआईटी, एनआईटी और देश के अन्य प्रतिष्ठित कॉलेजों में प्रवेश के लिए उपस्थित होने के लिए।

वित्तीय वर्ष	प्रमुख उपलब्धियां
	➢ एसईसीएल द्वारा ग्रीन हाईवे को अपनाना – एनएच-78 के साथ शहडोल से मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़ सीमा तक सड़क किनारे वृक्षरोपण (लगभग 100 किमी) एनएचएआई के माध्यम से कार्यान्वित किया गया।
	➢ बीसीसीएल द्वारा मोबाइल मेडिकल वैन के माध्यम से ग्रामीणों का उपचार – 1.19 लाख से अधिक लाभार्थी।
	➢ महंगे चिकित्सा उपकरणों की खरीद के माध्यम से सीआईएल द्वारा कोलकाता में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड डाइजेस्टिव साइंसेज (आईआईएलडीएस) की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता।
वित्तीय वर्ष 2017-18	• स्थापना के बाद से, मार्च 2018 तक सीआईएल की सहायक कंपनियों ने 38378 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में 96 मिलियन पौधे लगाए हैं।
	• सीआईएल के कई खनन क्षेत्रों जैसे ईसीएल के गुंजन पार्क, एसईसीएल के अनन्या वाटिका, एनसीएल के निगाही, डब्ल्यूसीएल के सौनेर, कायाकल्प वाटिका, सीसीएल में रजरप्पा इको पार्क आदि में ईको पार्क विकसित किए गए हैं।
	• सीआईएल में पहली बार पायलट पैमाने पर ड्रोन प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग का परीक्षण किया गया था, परिणाम बहुत उत्साहजनक थे और ड्रोन/यूएवी पर थारत सरकार की नीति का विमोचन के बाद नियमित उपयोग के लिए इस तकनीक को अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे।
	• वित्तीय वर्ष के दौरान सीधी भर्ती के माध्यम से 1143 प्रबंधन प्रशिक्षुओं का चयन किया गया।
	• पहली बार सीआईएल से पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 6.97% और 4.8% की वृद्धि के साथ, 606.89 मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन और 608.14 मीट्रिक टन की आपूर्ति करके, वित्त वर्ष 2019 को समाप्त होने वाले कोयला उत्पादन और ऑफ-टेक में 600 मीट्रिक टन का आंकड़ा पार किया था। वर्ष के दौरान कोयला उत्पादन में लगभग 7% की वृद्धि पिछले वित्त वर्ष की 2.4% की उत्पादन वृद्धि की तुलना में लगभग तीन गुना वृद्धि है।
	• हाल के वर्षों में उत्साहित उत्पादन गति इस तथ्य में स्पष्ट थी कि यह केवल तीन वर्षों में 500 मीट्रिक टन के उत्पादन से बढ़कर 600 मीट्रिक टन हो गया, जबकि कंपनी को 400 मीट्रिक टन से 500 मीट्रिक टन के उत्पादन में स्थानांतरित होने में सात साल लग गए।
वित्तीय वर्ष 2018-19	• वित्तीय बर्ष की समाप्ति से 5 दिन पहले, एनसीएल ने 100 एमटी के अपने उत्पादन लक्ष्य को पार कर लिया, इस प्रक्रिया में एसईसीएल और एमसीएल के बाद प्रतिष्ठित 100 एमटी उत्पादक कंपनियों में शामिल होने वाली सीआईएल की तीसरी सहायक कंपनी बन गई। एक और नए उच्च में एसईसीएल 150 एमटी से अधिक उत्पादन के निशान को क्रूज करने वाली सीआईएल की पहली सहायक कंपनी बन गई। ईसीएल और डब्ल्यूसीएल पहली बार 50 एमटी प्लस कंपनियां बनी हैं। एमओयू लक्ष्य के मुकाबले उत्पादन उपलब्धि 99.5% थी जबकि ऑफटेक में 99.7% लक्ष्य उपलब्धि देखी गई थी।
	• सीआईएल के सूत्रों ने पिछले वित्त वर्ष में आपूर्ति किए गए 454 मीट्रिक टन के मुकाबले 491 मीट्रिक टन कोयला ताप विद्युत संयंत्रों की आपुर्ति की, मात्रा में वृद्धि लगभग 37 मीट्रिक टन थी, जो साल-दर-साल 8.2% की वृद्धि थी। कुल ओबी निष्कासन 1161.99 एमसीयूएम था।
	• सीआईएल और एनएलसीएल ने अक्टूबर 2018 में 3,000 मेगावाट की सौर ऊर्जा उत्पादन और 2,000 मेगावाट क्षमता की ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए संयुक्त उद्यम (जेवी) कंपनी के गठन के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

वित्तीय बर्ष	प्रमुख उपलब्धियां
वित्त बर्ष 2018-19	• 3 अक्टूबर 18 को कोल इंडिया लिमिटेड ने 1 मिलियन अमेरिका डॉलर अर्थात 6.75 करोड़ रुपये के योगदान के माध्यम से, आईएसए के कॉर्पस फंड में जलवायु न्यूनीकरण प्रतिबद्धता के साथ अपनी हरित पहल को आगे बढ़ाने के एक हिस्से के रूप में, सीआईएल 'नेट जीरो कंपनी' बनने के लिए 3,000 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए कदम उठाए हैं।
	• उच्च क्षमता वाली हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी (एचईएमएम) के विभिन्न प्रकारों और आकारों की खरीद की प्रक्रिया को फास्ट ट्रैक किया गया, जिसे इसकी ओपनकास्ट खानों में संचालन में दबाया जाएगा-कोयला उत्पादन का प्रमुख स्रोत।
	• सीआईएल ने वर्ष 2018-19 के दौरान खान पट्टा क्षेत्र में 733 हेक्टेयर भूमि में 18.1 लाख पौधे रोपे।
	• 1.6 मिलियन टन/वर्ष की धुलाई क्षमता वाली दहीबारी वाशरी चालू की गई और 51% क्षमता का उपयोग किया गया।
	• सीआईएल की सहायक कंपनियों द्वारा वित्त पोषित दो प्रमुख रेल लिंक - ओडिशा में झारसुगुडा-बरपाली-सरडेगा और झारखंड में तोरी-शिवपुर चालु हो गए हैं।
	• एमडीएमएस (माइन डेटा मैने मेंट सिस्टम) पोर्टल की पीआर की सभी मुख्य विशेषताओं और चल रही परियोजनाओं के डेटा और पीआर प्रावधान के खिलाफ उनके प्रदर्शन को संग्रहीत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
	• 2018-19 के दौरान कुल पूंजीगत व्यय 7311.46 करोड़ रु.।
	• 2018-19 में पिछले वर्ष के 7,038.44 करोड़ रुपये की तुलना में कर पश्चात लाभ 17, 462.18 करोड़ रुपये था, 148% की वृद्धि दर्ज की, जबकि कर से पहले लाभ रु. वित्त वर्ष 2018-19 में विगत वर्ष के 27,125.46 करोड़ रुपये के मुकाबले 10,770.31 करोड़ रुपये थी, 152% वृद्धि हुई।
	• सीआईएल ने कुल मिलाकर अब तक की सर्वाधिक 1,40,603 करोड़ रुपये की सकल बिक्री और 92,896.08 करोड़ रुपये की शुद्ध बिक्री दर्ज की थी। सीआईएल की सभी अनुषंगियों ने वर्ष के दौरान लाभ अर्जित किया था।
	• रॉयल्टी, जीएसटी, सेस, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) और नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (एनएमईटी) और अन्य लेवी में 44,826.43 करोड़ रुपये भुगतान/समायोजित किया गया।
	• 9093.07 करोड़ रु. स्वीकृत पूंजी के साथ 69.88 एमटीवाई की क्षमता वाली 9 खनन परियोजनाएं और 6656.33 करोड़ रुपये स्वीकृत पूंजी के साथ 2 गैर खनन रेल परियोजनाएं सीआईएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए गए हैं।
	• 4110.418 हेक्टेयर वन भूमि वाले 18 प्रस्तावोंको चरण-I मंजूरी दी गई और 1045.47 होक्टेयर वाले 7 प्रस्तावों को चरण-II मंजुरी दी गई। सीआईएल की विभिन्न अनुषंगियों में 3398 हेक्टेयर भूमि का कब्जा है।
	• ईआरपी - सीआईएल ने 18 सिंतबर 2018 को सीआईएल ओर इसकी सहायक कंपनियों में एक मजबूत, अत्याधुनिक एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) और अस्पताल प्रबंधन प्रणाली के प्रणाली के डिजाइन और कार्यान्यन के लिए टेक महिंद्रा के साथ 270 करोड़ का अनुबंध किया।
	• '**मेक इन इंडिया पहल के** तहत, सीआईएल ने मैसर्स पर परीक्षण आदेश दिया था। बीईएमएल' स्वदेशी रूप से 190टी और 150टी डंपर विकसित करेगा। इन डंपरों की आपूर्ति और कमीशनिंग की गई है और इसके परिणामस्वरूप 22.15 करोड़ (लगभग) रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है।

वित्तीय बर्ष	प्रमुख उपलब्धियां
वित्त बर्ष 2018-19	• सीआईएल की सहायक कंपनी डब्ल्युसीएल की माइन रेस्क्यू टीम ने रूप के येकातेरिनबर्ग में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खान बचाव प्रतियोगिता (आईएमआरसी) 2018 में ''सबसे सक्रिय टीम'' का पुरस्कार हासिल किया।
	• सीआईएल ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कर्पेरेशन लिमिटेड का साथ सीआईएल की सभी अनुषंगियों/इकाइयों को एचएसडी की आपूर्ति पर 900/- रु. केएल। की एक समान छूट प्राप्त करने के लिए समझौता किया था। इस सकारात्मक कदम से 01-02-2019 से 31-03-2021 तक दो साल की अवधि के लिए लगभग 75.73 करोड़ रुपये की बचत होने की उम्मीद है।
	• वित्तीय वर्ष में बुक किया गया सीएसआर व्यय 416.47 करोड़ रुपये था- ➢ सीएसआर परियोजना ''थैलेसीमिया रोगियों में बीमारी का इलाज और बेहतर प्रबंधन'' के तहत गरीब मरीजों को राहत देते हुए छह प्रमुख अस्पातालों में जून, 2019 तक 105 अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण ऑपरेशन किए गए हैं।
	➢ क्षेत्र के समग्र विकास के लिए पुरुलिया जिले में ग्रामीण विकास परियोजना टेरी की एक अन्य मुख्य परियोजना है। अब तक 8,891 सोलर होम लाइटिंग सिस्टम, 100 सोलर स्ट्रीट लाइट, 7,342 बेहतर कुक स्टोव लगाए जा चुके हैं। स्वच्छता के क्षेत्र में जून 2019 तक लगभग 5,500 शौचालयों का निर्माण पूरा हो चुका है।
	➢ झारखंड के गोड्डा में 300 बिस्तरों वाले अस्पताल को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। ओडिशा में सीआईएल की सहायक कंपनी की वित्तीय सहायता से तालचेर में एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल आ रहे हैं।
	• गोरखपुर (यूपी) और सिंदरी (झारखंड) और बरौनी (बिहार) में प्राकृतिक गैस आधारित 1.27 एमटीपीए यूरिया संयंत्र स्थापित करने के लिए सीआईएल, एनटीपीसी, आईओसीएल, एफसीआईएल और एचएफसीएल से मिलकर हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) नामक एक संयुत्क्त उद्यम कंपनी का गठन किया गया है।
	• तालचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल) नाम की एक संयुक्त उद्यम कंपनी, जिसमें आरसीएफ, सीआइएल, गेल और एफसीआईएल शामिल हैं, का गठन पास के तालचर कोयला क्षेत्रों से कोयले का उपयोग करके एक भूतल कोयला गैसकरण आधारित एकीकृत उर्वरक परिसर स्थापित करने के लिए किया गया है।
	• वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, सीआईएल ने 399 प्रबंधन प्रशिक्षुओं / सीनियर अधिकारी (न्यूनतम) और 169 चिकित्सा अधिकारी को शामिल किया है।
वित्त बर्ष 2019-20	• कई चुनौतियों के बावजूद कि आपकी कंपनी को विशेष रूप से विस्तारित और भारी मानसून का सामना करना पड़ा, दीपका खान की बाढ़, विद्युत की कम मांग, मार्च 20 के अंतिम पखवाड़े में कोविड-19 आदि। कोल इंडिया ने कुल मिलाकर 602.14 मिलियन टन (मि.ट.) का उत्पादन किया।) लक्षित उत्पादन का 91% पूरा करना। कोयले की उठान 581.93 एमटी थी जो लक्ष्य प्राप्ति का 88% है। कुल ओबी निष्कासन 1154.33 एमसीयूएम था।
	• मार्च 2020 के दौरान 84.38 मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन किया, आपकी कंपनी ने अपनी स्थापना के बाद से एक महीने में अब तक के सबसे अधिक उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया है।
	• एसईसीएल ने लगातार दूसरे वर्ष 150 एमटी उत्पादन मील का पत्थर पार किया, ऐसा करने वाली एकमात्र सीआईएल उत्पादक कंपनी 150.55 एमटी उत्पादन कर रही है। एनसीएल ने पिछले वित्त वर्ष की अपनी सराहनीय उपलब्धि 2019-21 में भी दोहराई, जब उसने वित्तीय वर्ष के बंद होने से चार दिन पहले 106.25 मीट्रिक टन के अपने वार्षिक उत्पादन लक्ष्य को पार कर लिया। आखिरकार, एनसीएल ने

वित्तीय बर्ष	प्रमुख उपलब्धियां
वित्त बर्ष 2019-20	108.05 एमटी का उत्पादन किया। वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीन दिन पहले डब्ल्यूसीएल ने अपने वार्षिक उत्पादन लक्ष्य 56 मिलियन टन तक पहुंच गया। • 31 मार्च, 2020 को विद्युत घरों में कोयले का स्टॉक 45.01 मीट्रिक टन था, जो 28 दिनों की खपत के बराबर एक दशक में सबसे अधिक था, जो 22 दिनों के मानक से 6 दिन अधिक था। • कोल इंडिया ने 2019-20 के दौरान गैर-विनियमित क्षेत्रों (एनआरएस) के लिए अपनी आपूर्ति बढ़ा दी। वर्ष 2017-18 और 2018-19 से संबंधित इस क्षेत्र के लगभग 91% बैकलॉग बकाया रेक को मंजूरी दे दी। एनआरएस के 1 अप्रैल, 2019 को 5,143 बकाया रेक में से, कोल इंडिया ने वित्त वर्ष 2020 के समापन पर 4,661 रेक का परिसमापन किया। • **व्यवसाय करने में आसानी** को बढ़ावा देने के लिए, गैर-विद्युत उपभोक्ताओं के लिए आईआरएलसी (इरिवोकेबल रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट) भुगतान सुविधा शुरू की गई है। • 2019-20 के दौरान कुल पूंजीगत व्यय 6269.65 करोड़ रु. • कर पूर्व लाभ (पीबीटी) 24071.32 करोड़ रु., कर पश्चात लाभ (पीएटी) 16700.34 करोड़ रु., सकल बिक्री 134979.13 करोड़ रु. और शुद्ध बिक्री 89373.34 करोड़ रु.। • रॉयल्टी, जीएसटी, सेस, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) और नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (एनएमईटी) और अन्य लेवी के लिए 43058.72 करोड़ रुपये का भुगतान/समायोजित। • कोयला उत्पादन में तेजी लाने के लिए, कोल इंडिया और सहायक कंपनियों के बोर्ड द्वारा 2019-20 में 132.04 एमटीवाई की रेटेड क्षमता और 21244.55 करोड़ रुपये की स्वीकृत पूंजी के साथ 18 खनन परियोजना रिपोर्ट को मंजूरी दी गई है। • 3336.12 हेक्टेयर भूमि का कब्जा, जबकि कोयला असर क्षेत्र (सीबीए) (ए एंड डी) अधिनियम, 1957 की धारा 9 के तहत अधिसूचना 115.81 हेक्टेयर प्राप्त हुई। सीबीए (ए एंड डी) अधिनियम, 1957 की धारा 11 के तहत अधिसूचना - 631.58 हेक्टेयर थी। • **अनुबंध प्रबंधन पहल** जैसे ओसी, यूजी खानों के लिए एमडीओ दस्तावेजों को अंतिम रूप देना, 50.00 लाख रुपये तक की निविदाओं के लिए पूर्व-योग्यता को कार्यों और सेवाओं में बिना किसी तकनीकी और वित्तीय प्रमाण के नए बोलीदाता के प्रवेश के लिए हटा दिया गया है, पूर्व-योग्यता मानदंड कार्य अनुभव में 50% की कमी की गई है, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता में ढील दी गई है। • छत्तीसगढ़ में खरसिया से कोरिछापर तक पूर्वी रेल कॉरिडोर के तहत 44 किमी लंबी नई रेलवे लाइन 12 अक्टूबर 2019 को चालू हो गई। • झारसुगुड़ा-बरपाली खंड के दोहरीकरण के साथ-साथ झारसुगुड़ा में एक फ्लाईओवर परिसर और बारपाली में सात बल्ब एमसीएल में 2,900 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से आईबी कोलफील्ड्स से 65 मीट्रिक टन कोयला निकालने के लिए अनुमोदित किया गया है। • **'फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी'** प्रोजेक्ट्स के तहत मैकेनाइज्ड कोल ट्रांसपोर्टेशन और लोडिंग सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए कदम उठाए हैं। पहले चरण में, 12505 करोड़ रुपये के अनुमानित पूंजीगत व्यय के साथ 406 एमटीवाई क्षमता वाली 35 एफएमसी परियोजनाएं। • ईआरपी - ग्लोबल बिजनेस ब्लूप्रिंट सीआईएल स्थापना दिवस (1 नवंबर 2019) को माननीय संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री द्वारा जारी किया गया था। • कोयला गुणवत्ता उपाय: तीसरे पक्ष की एजेंसी के माध्यम से कोयले की गुणवत्ता का आकलन लागू किया गया है। वर्तमान में विद्युत उपयोगिताओं को 99% आपूर्ति नमुनाकरण के तहत कवर की जा रही है। कंपनियों की 49 प्रयोगशालाओं को एनएबीएल से मान्यता मिल चुकी है।

वित्तीय बर्ष	प्रमुख उपलब्धियां
वित्तीय बर्ष 2019-20	• एचईएमएम खरीद: 5900 करोड़ रुपये से अधिक की भारी अर्थ मूविंग मशीनरी की खरीद के लिए निविदाएं। कोयला उत्पादन में वृद्धि और एचईएमएस की आयु प्रो.फाइल में सुधार के लिए को अंतिम रूप दिया गया है। • नियमावली और नीतियों का अद्यतनीकरण: कोल इंडिया लिमिटेड ने 2004 में जारी अपनी खरीद नियमावली की व्यापक समीक्षा और अद्यतन किया है। इसके अलावा, पहली बार, स्क्रैप के निपटान के लिए एक समान नीति को अंतिम रूप दिया गया है और सीआईएल में कार्यान्वयन के लिए परिचालित किया गया है। • **रूस के साथ समझौता ज्ञापन:** भारत के माननीय प्रधान मंत्री और रूसी संघ के माननीय राष्ट्रपति की गरिमामयी उपस्थिति में, कोर्किंग कोल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, विकास और संचालन के व्यवसाय में उद्यम करने के लिए द्विपक्षीय संबंधों का लाभ उठाने के लिए एक रूसी सरकारी एजेंसी सुदूर पूर्व निवेश और निर्यात एजेंसी और कोल इंडिया लिमिटेड के बिच रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र में व्लादिवोस्तोक, रूस में 4 सितंबर, 2019 को एक द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) निष्पादित किया गया था। • **ईज ऑफ डूइंग बिजनेस:** विद्युत उत्पादकों के लिए कोयले की आपूर्ति के लिए ट्रिगर स्तर को एसीक्यू के 75% से बढ़ाकर 80% करने सहित कई पहल, वित्त वर्ष 2020–21 की दो तिमाहियों के लिए प्रदर्शन प्रोत्साहन माफ किया, विद्युत और एनआरएस उपभोत्काओं के लिए यूसेंस एलसी पेश किया, एनआरएस लिंकेज नीलामी मार्ग के माध्यम से एफएसए के तहत सड़क मोड के माध्यम से कोयला उठाने में कठिनाई वाले उपभोक्ताओं और विशेष फॉरवर्ड ई–नीलामी के तहत विद्युत उपभोत्काओं के लिए सड़क से रेल मोड में कोयले के परिवहन के तरीके में बदलाव की व्यवस्था प्रदान की; और वित्त वर्ष 2020–21 की दूसरी तिमाही तक सभी ई–नीलामी योजनाओं के लिए आरक्षित मूल्य को अधिसूचित मूल्य तक कम कर दिया। • **कोविड–19 के दौरान किए गए कल्याणकारी उपाय :** ➢ लॉकडाउन अवधि के दौरान 2,81,815 पके हुए भोजन के पैकेट और 1,36,168 पैक्ड राशन दलितों और अरूरतमंदों को वितरित किए। ➢ कोल इंडिया के 35 अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं में कोयला उत्पादक आठ राज्यों में अस्पतालों में कोरोना संदिग्ध मामलों और कोरोना पॉजिटिव मामलों के लिए अतिरिक्त 1234 बिस्तर अलग रखे गए हैं। ➢ झारखंड के धनबाद में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के केंद्रीय अस्पताल, केंद्रीय अस्पताल, गांधीनगर, झारखंड और क्षेत्रीय अस्पताल, रामगढ़, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, झारखंड को कोविड अस्पताल में बदल दिया गया है और मरीजों के इलाज के लिए राज्य सरकार को सौंप दिया गया है। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने ओडिशा के भूवनेश्वर में एक अत्याधुनिक 500 बिस्तरों वाले एसयूएम–कोविड अस्पताल को पूरी तरह से वित्त पोषित किया है। कोरबा, छत्तीसगढ़ में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के 50 बिस्तरों वाले मुख्य अस्पताल को कोविड अस्पताल में बदल दिया गया है और कोविड से लड़ने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को सौंप दिया गया है। इसके अलावा, एसईसीएल ने जिला अस्पताल, बिलासपुर को 100 बिस्तरों वाले विशेष कोविड उपचार केंद्र में स्तरोन्नत करने के लिए 4.08 करोड़ रुपये का योगदान दिया है। इसके अलावा, एसईसीएल ने राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, अंबिकापुर को 100 बिस्तरों वाले विशेष कोविड उपचार केंद्र में स्तरोन्नत करने के लिए 4.19 करोड़ रुपये का भी योगदान दिया। ➢ सीआईएल की सहायक कंपनियों ने कोविड–19 से लड़ने के लिए अपने कर्मचारियों और इसके परिचालन क्षेत्रों और इसके आसपास रहने वाले लोगों को 15,42,982 मास्क और 63,256 लीटर हैंड सैनिटाइजर वितरित किया हैं।

वित्तीय बर्ष	प्रमुख उपलब्धियां
	➢ सीआईएल की सहायक कंपनियों ने कोविड महामारी से लड़ने के लिए एन 95 मास्क, वेंटिलेटर, पीपीई सूट, थर्मल स्कैनर और ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे।
	➢ आवासीय कॉलोनियों, ठेका श्रमिकों के शिविरों और आसपास के गांवों को साफ करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक के 'फॉग कैनन्स' को सेवा में लगाया जा रहा है।
	• **सीआईएल और उसकी अनुषंगियों ने 2019-20 के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर 587.84 करोड़ रुपये खर्च किये।** सीआईएल ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास के लिए निम्नानुसार महत्वपूर्ण योगदान दिया है:
	➢ चक्रवात फैनी के कारण क्षतिग्रस्त हुई विद्युत पारेषण लाइनों के पुनर्स्थापन के लिए ओडिशा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओपीटीसीएल) को 50.32 करोड़ रुपये।
	➢ कर्नाटक के धारवाड़ और बागलकोढ जिलों में बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुए सरकारी स्कूल भवनों के पुनर्निर्माण के लिए 25 करोड़ रु.।
	➢ असम के बाढ़ प्रभावित माजुली जिले में आजीविका पुनर्वास परियोजना और जल एम्बुलेंस की खरीद के लिए 16.50 करोड़ रुपये।
	➢ कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए पीएम केयर्स फंड में 160 करोड़ रुपये का योगदान दिया।
वित्त बर्ष 2019-20	➢ कोल इंडिया की दो सहायक कंपनियों, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड को राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में योगदान के लिए भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सीसीएल को खेल को बढ़ावा देने के लिए और एमसीएल के स्वास्थ्य, सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता के लिए पुरस्कार मिला।
	• कोल इंडिया ने 2019-20 में 19,72,788 पौधे लगाने के लक्ष्य के मुकाबले 812.98 हेक्टेयर भूमि पर 19,76,618 पौधे रोपे। अपने खनन क्षेत्रों के आसपास के समुदायों को सिंचाई और अन्य घरेलू उपयोगों के लिए पानी उपलब्ध कराने के कोल इंडिया के प्रयासों से वित्त बर्ष के दौरान 7.48 लाख आबादी लाभान्वित हुई।
	• 62.035 एमचीवाई की वृद्धिशील क्षमता वाली 31 खनन परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी (ईसी), 2011-12 के बाद से अब तक सबसे अधिक।
	• 952.04 हेक्टेयर की 7 परियोजनाओं के लिए चरण-। वानिकी मंजूरी (एफसी) को अनुमोदित किया गया था और 1,248.86 हेक्टेयर की 5 परियोजनाओं के लिए चरण-।। वानिकी मंजूरी (एफसी) को अनुमोदित किया गया था। चरण-। वानिकी मंजूरी (एफसी) 2014-15 के बाद सबसे ज्यादा है।
	• 2019-20 के दौरान, सीआईएल ने सीधी भर्ती के माध्यम से 77 प्रबंधन प्रशिक्षुओं और 138 चिकित्सा अधिकारियों को शामिल किया था।
वित्तीय बर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2020-21 ने कोविड-19 महामारी के रूप में पहले कभी नहीं देखी गई चुनौती पेश की। न केवल कंपनी के लिए बल्कि देश के लिए भी सामना करना एक कठिन स्थिति थी। वास्तव में, यह अमूतपूर्व चुनौतीपूर्ण एक वैश्विक घटना थी। कर्मचारियों का स्वास्थ्य और कल्याण मुख्य प्राथमिकता थी। चिकित्सा सहायता के रूप में बिस्तरों की स्थापना को आगे बढ़ाया गया है। सीएसआर बैनर के तहत युद्धस्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं का निर्माण किया गया है। लॉकडाउन के कारण, कोयले की कम मांग के कारण ऑफटेक एक बड़ी चुनौती थी।
	• सीआईएल ने 596.22 मिलियन टन (मि.ट.) का उत्पादन किया, यह एमओयू लक्ष्य की 90.34% उपलब्धि थी।

वित्तीय बर्ष	प्रमुख उपलब्धियां
वित्तीय बर्ष 2020-21	• कोयले की कम मांग के बावजूद, सीआईएल 574.48 एमटी की आपूर्ति कर सका जो कि वर्ष के दौरान लक्ष्य उपलब्धि का 87.04 प्रतिशत है।
	• प्रदर्शन की गति वर्ष की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर 20) में भी 6.3% उत्पादन वृद्धि और 9% ऑफ-टेक वृद्धि के साथ बनी रही।
	• एनसीएल ने लगातार छठे वर्ष अपना वार्षिक उत्पादन लक्ष्य हासिल कर लिया है। एसईसीएल ने अपने उत्पादन की गति को लगातार तीसरे वर्ष 150 मीट्रिक टन के स्तर को पार किया।
	• 2020-21 के दौरान ओबीआर वॉल्यूम के लिहाज से अब तक का सबसे ज्यादा (1344.68 एमसीयूएम) था और एक दशक में वृद्धि प्रतिशत के लिहाज से दूसरा सबसे ज्यादा (16.49) था।
	• वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 27.60 एमटीवाई की क्षमता वाली 9 खनन परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं।
	• सीआईएल ने अपने पूंजीगत व्यय को वित्त-वर्ष 20 में 6,269.65 करोड़ की तुलना में अप्रत्याशित तौर पर दोगुना से अधिक बढ़ाकर वित्त-वर्ष 21 में 13,283.83 करोड़ रूपये किया, कोविड की मंदी के बीच भी 111.88% की वृद्धि दर्ज की गई।
	• सीआईएल ने 18,009.24 करोड़ रूपये का कर पूर्व लाभ (पीबीटी), 12,702.17 करोड़ रूपये का कर-पश्चात लाभ, 1,26,786.13 करोड़ रूपये की सकल बिक्री और 82,710.32 करोड़ रूपये की शुद्ध बिक्री हासिल की।
	• रॉयल्टी, जीएसटी, जीएसटी मुआवजा उपकर, उपकर, जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ), राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एनएमईटी) और अन्य लेवी में 41,987.79 करोड़ रूपये का भुगतान/समायोजित।
	• **आपूर्ति बढ़ाने के उपाय :** ➢ पूरे वित्त वर्ष, 21 के लिए विद्युत क्षेत्र को एफएसए के तहत आपूर्ति किए गए कोयले की अतिरिक्त मात्रा के लिए प्रदर्शन प्रोत्साहत की छूट।
	➢ विशेष फॉरवर्ड ई-नीलामी और विशेष ई-नीलामी के लिए विद्युत क्षेत्र और गैर-विनियमित क्षेत्र के उपभोक्ताओं (एनआरएस) के लिए मीयादी एलसी सुविधा शुरू की गई थी।
	➢ सभी ई-नीलामी विंडो के तहत आरक्षित मूल्य वित्त वर्ष 2011 के पहले छह महीनों के दौरान अधिसूचित मूल्य के बराबर रखा गया था, जिससे कोयला उपभोत्काओं को अतिरिक्त मात्रा में उठाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
	➢ मासिक अनुसूचित मात्रा पर ध्यान दिए बिना एनआरएस उपभोक्ताओं के लिए पूरे वित्तीय वर्ष में उठाने के विकल्प में लचीलापन लाया गया।
	➢ कोयले के परिवहन के तरीके को सड़क से रेल और इसके विपरीत में बदलने के लचीलेपन की अनुमति दी गई थी। • **'आत्मनिर्भर भारत' के तहत कोयले के आयात पर अंकुश लगाने की पहल :**
	➢ अक्टूबर 20 में विशेष रूप से कोयला आयातकों के लिए एक नई ई-नीलामी विंडो खोलना।
	➢ घरेलू कोयले के साथ कोयले की आयात की प्रतिस्थापित करने के लिए, सम्मिश्रण उद्देश्य के लिए, सहायक कोयला कंपनियों को उनसे जुड़े 17 विद्युत संयंत्रों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी गई।
	➢ फ्लेक्सी-यूटिलाइजेशन के तहत केंद्रीय और राज्या जेनकोस को अतिरिक्त कोयले का आवंटन, जिससे वे कोयले के आयात को टाल सकें।

वित्तीय बर्ष	प्रमुख उपलब्धियां
वित्तीय बर्ष 2020-21	➢ विद्युत संयंत्रों के लिए वार्षिक अनुबंधित मात्रा (एसीक्यू) को 90% से मानक आवश्यकता के 100% तक बढ़ाना।
	➢ एफएसए के मुकाबले एसीक्यू के 100% तक गैर-विनियमित क्षेत्रों को कोयले की बढ़ी हुई मात्रा की पेशकश करना।
	➢ विद्युत क्षेत्र के लिए विशिष्ट एफएसए के तहत ट्रिगर स्तर को 75% से बढ़ाकर 80% करना। पहल के सेट के संचयी प्रयास के परिणामस्वरूप 90 मीट्रिक टन केयले के आयात पर अंकुश लगा। अगर आपकी कंपनी ने इस आविष्कार को नहीं अपनाया होता, तो ग्राहकों के पास आयात से कोयले के स्रोत के अलावा कोई विकल्प नहीं होता।
	• सीआईएल ने वित्त वर्ष 2021 में पांच ई-नीलामी विंडो के तहत 124 एमटी कोयला बुक किया है, जो एक सर्वकालिक उच्चलम रिकॉर्ड है।
	• तीसरे पक्ष के नमूना विश्लेषण के अनुसार, बेहतर गुणवत्ता वाले कोयले की आपूर्ति के लिए सीआईएल की पतिद्धता एक सकारात्मक उछाल दर्शांती है क्योंकि वित्त बर्ष 2021 के दौरान ग्रेड अनुरूपता 59% से बढ़कर 63% हो गई। बर्ष के दौरान आपूर्ति किए गए कोयले की औसत गुणवत्ता कोयले के घोषित ग्रेड, सीआईएल गुणवत्ता बोनस से बेहतर थी।
	• वित्त बर्ष 2021 में आपकी कंपनी द्वारा 332.77 एमटी की स्वीकृत क्षमता और 220.12 एमटी की वृद्शील क्षमता के साथ अब तक की सबसे अधिक 36 खनन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी।
	• बर्ष के दौरान 2,675.43 हेक्टेयर भूमि पर आधिपत्य हासिल किया गए।
	• सात 150 टन डंपर और आठ 190 टन डंपर की खरीद के लिए बीईएमएल लिमिटेड के साथ लगभग 400 करोड़ रु. के दो खरीद समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
	• वर्ष के दौरान 10 भूतल खनिकों (सरफेस माइनर) को विभागीय रूप से तैनात किया गया था और 0.91 मीट्रिक टन/वर्ष की कुल क्षमता के 2 सतत खनिक चालू की गई।
	• सीआईएल ने सभी 35 एफएमसी परियोजनाओं के लिए सफलतापूर्वक निविदाएं और साथ ही एलओए/कार्य आदेश जारी किए हैं जिनमें आरएलएस के साथ सीएचपी-एसआईएलओ और भारतीय रेलवे नेटवर्क के साथ इसकी रेल कनेक्टिविटी शामिल है। 11,500 करोड़ रूपये की अनुमानित पूंजी लागत पर, इन परियोजनाओं में प्रति बर्ष 414.5 मीट्रिक टन कोयला निकालने की क्षमता होगी।
	• बर्ष के दौरान खरसिया-धरमजयगढ़ (0-74 किमी) रेल लाइन के कोरीचापार-धर्मजयगढ़ खंड (45-74 किमी) के बीच इंजन का ट्रायल रन पूरा किया गया।
	• झारसुगुड़ा-बरपाली रेल लाइन के दोहरीकरण के साथ-साथ बरपाली में 7 लीडिंग बल्व और तोरी-शिवपुर रेल लाइन की तिगुना करने को मंजूरी दी गई है।
	• शीआईएल ने वित्त वर्ष 2021 में अपने खनन क्षेत्रों में 861.81 हंक्टेयर हरित आवरण प्राप्त करते हुए बड़ें पैमाने पर वृक्षारोपण किया है। यह वर्ष के लिए लक्षित 739.5 हेक्टेयर की 116% अपलब्धि का प्रतिनिधित्व करता है। बर्ष के दौरान कुल 19.89 लाख पौधे लगाए गए हैं।
	• सीआईएल की विभिन्न अनुषंगियों की खानों से निकाले गए खान के पानी के सामुदायिक अपयोग में पिछले बर्ष की तुलना में 40% की वृद्धि हुई है जिससे 703 गांवों की 10,91,583 आबादी लाभान्वित हुई है।
	• सीआईएल ने सौर ऊर्जा नीलामी की प्रतिस्पर्धी बोली में अपनी पहली भागीदारी में गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड द्वारा आयोजित रिवसे ई-नीलामी में 100 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना जीती थी। यह हरित उर्जा उत्पादन में सीआईएल के प्रवेश की दिशा में एक कदम है।

वित्तीय बर्ष	प्रमुख उपलब्धियां
वित्तीय बर्ष 2020-21	• 31 खनन परियोजनाओं और 2 वाशरियों के लिए क्रमश: 27.80 एमटीवाई और 3 एमटीवाई की वृद्धिशील क्षमता के लिए पर्यावरण मंजूरी।
	• कुल 1,387.06 हेक्टेयर वन भूमि के 8 प्रस्तावों के लिए चरण-II वानिकी मंजूरी (एफसी) प्राप्त की गई यी और 277.15 हेक्टेयर के 1 प्रस्ताव के लिए चरण-I वानिकी मंजरी (एफसी) प्राप्त की गई थी।
	• सीआईएल और उसकी अनुषंगियों ने सीएसआर गतिविधियों पर रू.553.85 करोड़ रू. किये। वर्ष के कुल खर्च किए गए सीएसआर में से, 48.57% विशेष रूप खनन क्षेत्रों के निकट के समुदाय के लाभ के लिए कोविड राहत अपायों पर खर्च किया गया था।
	➢ लगभग 1500 बिस्तरों की स्थापना इसे भारतीय कॉरपोरेटसो के बीच सबसे बड़े मोबिलाइजर्स में से एक बनाती है।
	➢ सीएसआर के प्रयास महामारी क दूसरी लहर के दौरान लगातार जारी रहे और साथ ही कुल बिस्तरीं की संख्या दोगुनी से अधिक 3,900 हो गई।
	➢ अपने और सरकारी अस्पतालों सहित 27 अस्पतालों में 29 ऑक्सीजन पैदा करने वाले संमंत्र स्थापित करने का निर्णय।
	➢ एमसीएल ने भुवनेश्वर में 525 बिस्तरों का अस्पताल और लखनपुर में 150 बिस्तरों का अस्पताल स्थापित किया है।
	➢ सीआईएल ने एसईसीएल के तहत अंबिकापुर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों और कर्नाटक के धारवाड़ के एक अन्य अस्पताल को 100 बिस्तरों वाले कोविड अपचार केंद्रों में बदल दिया है।
	➢ एनसीएल ने उत्तर प्रदेश सरकार को 50 एम्बुलेंस प्रदान की हैं।
	➢ जरूरतमंद समुदाय को 3 लाख से अधिक मुप्त भोजन के पैकेट, 17.56 लाख से अधिक मास्क और 80,800 लीटर से अधिक हैंड सैनिटाहजर का वितरण किया।
	➢ कोविड की पहली लहर के दौरान शुरू किए गए स्वास्थ देखभाल प्रयासों को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है और चिकित्सा सुविधाओं और बुनियादी ढांचे का विस्तार किया जा रहा है।
	➢ थैलेसीमिया और अप्लास्टिक एनीमिया बच्चों के इलाज के लिए थैलेसीमिया 'बाल सेवा योजना' का दुसरा चरण शुरू किया गया। इस कदम से 200 से अधिक वंचित रोगियों को 20 करोड़ रूपये के अनुदान पर लाभ होने की अम्मीद है।
	➢ 1,804 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों और 9 सरकारी इंटर कॉलेजों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार की शुरूआत की। एमसीएल ने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में 14,298 फर्नीचर का वितरण शुरू किया है।
	• विविधीकरण : एक अन्य पहल के तहत, सीआईएल भूतल कोयला गैसीकरण, सौर ऊर्जा उत्पादन, सौर पीवी विनिर्माण, एल्युमिनियम गलाने में उद्यम करने की संभावनाएं तलाश रहा है।
	• वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, सीआईएल ने गैर-कार्यकारी से कार्यकारी संवर्ग में विभागीय पदोन्नति/चयन के माध्यम से खनन संवर्ग में 257 वरिष्ठ अधिकारी (खनन) - ई 2 ग्रेड को पदोन्नत/चयनित किया है। सीआईएल ने प्रबंधन प्रशिक्षुओं की भर्ती के लिए सं. 01/2019 (एमटी-2019) दिसंबर 2019 में 11 विषयों में 1326 रित्कियों को अधिसूचित किया। 11 विषयों में उंतिम रूप से चयनित 1286 सफल अम्मीदवारीं की सूची प्रकाशित की गई है।

वित्तीय बर्ष	प्रमुख उपलब्धियां
वित्तीय बर्ष 2021-22 (ऑकड़े अनंतिम हैं)	• 622.6 मिलियन टन (मि.ट.) का सर्वकालिक रिफॉर्ड उच्च कोयला उत्पादन और 661.9 मीट्रिक टन का कोयला ऑफटेक (उठाव)। समवर्ती रूप से, ओवरबर्डन निष्कासन बढ़कर 1,366 मिलियन क्यूबिक मीटर (M.CuM) हो गया, जी अब तक का एक और उच्च स्तर है। • देश की उप्तादन कंपनियों की बढ़ती कोयले की मांग के बीच, विद्युत क्षेत्र को सीआईएल की आपूर्ति 95.4 मीट्रिक टन की भारी वृद्यि के साथ रिकॉर्ड 540.4 मिलियन टन (मि.ट.) तक पहुंच गई। यह वित्त वर्ष 2021 की 445 मीट्रिक टन आपूर्ति की तुलना में 21.4% की वृद्धि दर्शाता है। वित्त वर्ष 22 में तीव्र 95.4 मि.ट. आपूर्त्ति विस्तार पिछले सात वर्षो की अवधि के दौरान प्राप्त सामूहिक वृद्धि से अधिक है। विद्युत क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति 2013-14 में 353.8 मीट्रिक टन से बढ़कर 2020-21 में बढ़कर 445 मीट्रिक टन हो गई, जिसमें 91.2 मीट्रिक टन की वृद्धि दर्ज की गई। **कोयला उप्तादन :** • 2018-19 में दर्ज 606.9 मीट्रिक टन के पिछले उच्च स्तर को पार करते हुए कंपनी के लिए 622.6 मीट्रिक टन का कोयला उप्तादन अब तक का अच्चतम स्तर है। वर्ष का कुल उप्तादन 26.4 मीट्रिक टन की वृद्धि दर्शाता है जो कि पिछले वित्त वर्ष के 596.22 मीट्रिक टन की तुलना में 4.4% की वृद्धि है। • लक्ष्य का 103 प्रतिशत हासिल कर 168.2 एमटी के उप्तादन के साथ एमसीएल शीर्ष प्रदर्शकर्ता था। एमसीएल ने भी वित्त वर्ष 2021 की तुलना में 13.6% की मजबूत वृद्धि दर्ज की। • सीआईएल की पांच सहायक कंपनियों ने वित्त वर्ष 21 के उप्तादन में वृद्धि दर्ज की। वे बीसीसीएल (23.8%), सीसीएल (10.0%) एनसीएल (6.4%), डब्ल्यूसीएल (14.8%) और एमसीएल (13.6%) है। • बीसीसीएल, एनसीएल और एमसीएल 100% से अधिक की उपलब्धि के साथ वित्त वर्ष 22 के अपने-अपने उत्पादन लक्ष्य से आगे निकल गए हैं। **कोयले का ऑफटेक (उठाव)** • हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्श के दौरान 661.9 मीट्रिक टन कोयले की उठान में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 87.4 मीट्रिक टन की भारी वृद्धि हुई है। यह एक साल में निरपेक्ष अवधि में अब तक की सबसे ऊंची छलांग है, हससे पहले का सबसे अच्छा प्रदर्शन 2015-16 में 45.1 मीट्रिक टन था। • यह उपलब्धि वित्त वर्ष 2021 की तुलना में 15.3% की वृद्यि दर्शाती है जब उठान 574.48 मीट्रिक टन था। • 87.4 मीट्रिक टन की वार्षिक वृद्धिशील वृद्धि पिछले छह वर्षों की संचयी वृद्धि 2014-15 में 489.38 मीट्रिक टन से बढ़कर 2020-21 में 574.48 मीट्रिक टन हो गई, जो 85.1 मीट्रिक टन थी। • सीआईएल की सात कोयला उत्पादक कंपनियों में से छह ने पिछले वित्त वर्ष के उठान को काफी अंतर से पार कर लिया। अधिकतम वृद्धि के क्रम में वे एमसीएल (29.4 मि.ट.), एनसीएल (17.0 मि.ट.), एसईसीएल (16.9 मि.ट.), डब्लूसीएल (14.5 मि.ट.), वीसीसीएल (9.2 मि.ट.), और सीसीएल (6.5 मि.ट.) हैं। • बीसीसीएल एकमात्र सहायक कंपनी के रूप में उभरी है जिसने वित्त वर्ष 22 के 32.3 एमटी के ऑक-टेक लक्ष्य को 101% उपलब्धि के साथ पार कर लिया है। • विद्युत मंत्रालय और केंन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अनुमानित 99% मांग को पुरा करने के लिए विद्युत क्षेत्र में कोयला प्रेषण 540.4 मीट्रिक टन के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर था।

वित्तीय बर्ष	प्रमुख उपलब्धियां
वित्तीय बर्ष 2021-22 (ऑकड़े अनंतिम हैं)	**अन्य विपणन उपलब्धियां और पहल**
	• बेहतर गुणवत्ता वाले कोयले की आपूर्ति के प्रयासों में सकारात्मक उछाल दिखाई दिया क्योंकि 31.03.2022 तक प्राप्त तीसरे पक्ष के नमुना विश्लेषण परिणामों के अनुसार, ग्रेड अनुरूपता अप्रैल, 21 से मार्च, 22 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में 63% से बढ़कर 65% हो गई।
	• 2020-21 की इसी अवधी के दौरान 241.4 रेक/दिन के मुकाबले दैनिक औसत रेल लोडिंग 271.2 रेक/दिन के उच्चतम स्तर पर थी, जिसमें 12% की वृद्धि दर्ज की गई।
	• विद्युत क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए रेक लोडिंग भी पिछले वर्ष की इसी अवधी के दौरान 203.4 रेक/दिन के मुकाबले अब तक के उच्चतम स्तर 243.1 रेक/दिन पर भी, जिसमें 20% की वृद्धि दर्ज की गई।
	• रेल और सड़क मार्ग से प्रेषण में क्रमश: 13% और 38% की वृद्धि हुई।
	• सीआईएल ने उत्पादन इकाइयों में कोयले के स्टॉक को बढ़ावा देने के लिए दो दौर में कुल 11.2 मीट्रिक टन अतिरिक्त कोयले की पेशकश की है, जब सितंबर, 21 में विद्युत उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई थी। सीआईएल की अत्यधिक भंडार वाली खानों से सड़क-सह-रेल मोड के माध्यम से 12 केंन्द्रीय और राज्य के जेनको को प्रस्ताव दिया गया था।
	• उपरोक्त अतिरिक्त प्रस्ताव के कारण, विद्युत क्षेत्र के लिए गुडस शेड और निजी वाशरी से लिफ्टिंग ने पिछले वर्ष की तुलना में क्रमश : 131% और 133% की भारी वृद्धि हासिल की है।
	• विशेष फॉरवर्ड ई-नीलामी विंडो के माध्यम से 38.5 मीट्रिक टन कोयले का उठाव, वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि अब तक 50% थी।
	• सीआईएल ने वित्त वर्ष की शुरूआत 99.13 एमटी स्टॉक के साथ की थी, जो 2021-22 के दौरान 38.42 एमटी का परिसमापन करने में कामयाब रही।
	• विद्युत और एनआरएस उपभोक्ताओं के साथ-साथ विशेष फॉरवर्ड और विशेष ई-नीलामी के लिए शुरू की गई यूसेंस एलसी सुविधा को वित्त वर्ष 2022-23 तक बढ़ा दिया गया है।
	• विद्युत संयंत्रों की वार्षिक अनुबंधित मात्रा को दुरदराज के संयंत्रों के लिए 90% और तटीय विद्युत संयंत्रों के लित्र 70% के स्थान पर मानक आवश्यकता के 100% के स्तर तक बढ़ाया गया था (विद्युत अधिनियम की धारा 62 के तहत आने वाले संयंत्रों के लिए) सीईए द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार।
	• इच्छुक विद्युत संयंत्रों के लिए वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आपूर्ति का न्यूनतम सुनिश्चित स्तर मौजूदा 75% से बढ़ाकर 80% कर दिया गया है।
	• एफएसए के तहत विद्युत क्षेत्र के लिए निष्पादन प्रोत्साहन 31 मार्च 2022 तक माफ कर दिया गया, बशर्ते कोयला मूल्य का अग्रिम भुगतान किया जाए।
	• विद्युत क्षेत्र से कोयले की मांग में वृद्धि के बावजूद, सीआईएल ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान ई-नीलामी की विभिन्न खिड़कियों के तहत 108 मीट्रिक टन कोयले का आवंटन अधिसूचित मूल्य से 88% के औसत प्रीमियम के साथ किया। इससे अधिसुचित मूल्य से अधिक 12,188 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ।

वित्तीय बर्ष	प्रमुख उपलब्धियां
वित्तीय बर्ष 2021-22 (ऑकड़े अनंतिम हैं)	• इस वित्तीय वर्ष के दौरान, गैर-विद्युत अधिसूचित मूल्य पर 14% औसत प्रीमियम के साथ ट्रेंच-वी एनआरएस लिंकेज नीलामी में 44 मीट्रिक टन से अधिक लंबी अवधि के लिंकेज बुक किए गए हैं। • 4.4 एमटी की आवंटित मात्रा के लिए त्रैमासिक बी (viii a) नीलामी के 4 चरणों को सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है। • सीआईएल ने कई खिड़कियों को जोड़कर एकल खिड़की ई-नीलामी शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे कोयले की बाजार संचालित कीमत की प्रक्रिया और खोज में अधिक पारदर्शिता आने की उम्मीद है। **परियोजना रिपोर्ट का अनुमोदन** कुल 16 कोयला खनन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 7 ग्रीन फील्ड परियोजनाएं और 9 विस्तार परियोजनाएं हैं। संयुक्त रूप से, उनकी कुल क्षमता 99.84 एमटीवाई और वृद्धिशील क्षमता 56.66 एमटीवाई है। कुल पूंजी निवेश रु. 18,309.19 करोड़ जबकि अतिरिक्त पूंजी निवेश रु. 16,708.97 करोड़ है। **एमडीओ के माध्यम से उत्पादन में वृद्धि** 170 एमटीवाई की संयुक्त लक्षित क्षमता वाली 15 एमडीओ परियोजनाओं (10 ओसी और 5 यूजी) में से 96 एमटीवाई क्षमता की 5 परियोजनाओं के लिए कार्य आदेश जारी किए गए हैं। शेष परियोजनाएं प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं। ***फस्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोजेक्टस*** *चरण -I में, 82 एमटीपीए क्षमता की 6 एफएमसी परियोजनाएं अब तक चालू की गई हैं, जिनमें से 35 की कुल क्षमता 414.5 एमटीपीए है।* *दुसरे चरण में 57 एमटीपीए की 9 परियोजनाओं में से वित्तीय वर्ष 2021-22 में 14 एमटीपीए क्षमता की 3 परियोजनाओं के लिए कार्य आवंटित किया गया है। वे कुमारडीह-1 एमटीपीए के बी सीएचपी, 3 एमटीपीए के हुरा सीएचपी-सिलो और 10 एमटीपीए के मुंगोली-निर्गुडा सीएचपी-सिलो हैं।* ***रैल अवसंरचना*** विशेष रूप से उच्च विकास क्षमता वाली खानों से रेल माध्यम से कोयले का निर्बाध परिवहन सुनिश्चित करने के लिए, सीआईएल ने नई रेल लाइनों के निर्माण में निवेश किया है। FY2021-22 में कुछ प्रमुख घटनाक्रम हैं: एमसीएल के तालचेर कोलफील्ड्स में देउलबेड़ा साइडिंग के साथ लिंगराज साइलो की रेल कनेक्टिविटी 18 मई, 2021 को चालू की गई थी। चरण-I की छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड परियोजना के तहत, 74 किमी स्ट्रेच कॉरिडोर खरसिया-धर्मजयगढ़ 21 जून 2021 को चालू किया गया था। 26 मार्च को सीईआरएल के धर्मजयगढ़ फ्रेट टर्मिनल से पहला कोयला रेक लोड किया गया था। वित्त वर्ष-22 के दौरान कुसमुंडा पीएच-II और सोनपुर बाजारी के सीएचपी-एकआईएलओ के लिए रेल संपर्क चालू किया गया। **कोयले की धुलाई** 5 एमटीवाई के अत्याधुनिक मधुवन वाशरी का उद्घाटन 24 मार्च को किया गया है।

वित्तीय बर्ष	प्रमुख उपलब्धियां
वित्तीय बर्ष 2021-22 (ऑकड़े अनंतिम हैं)	बीसीसीएल का धुला हुआ कोकिंग कोल उत्पादन 1.21 मीट्रिक टन पर पिछले वित्त वर्ष के 0.75 मीट्रिक टन की तुलना में 61.2% की वृद्धि दर्ज की गई। इससे सीआईएल के कुल धुले हुए कोकिंग कोल का उत्पादन 35.6% बढ़कर 1.61 मिलियन टन हो गया जो कि तीन साल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। कोकिंग कोल वाशरीज को कच्चे कोयले की आपूर्ति पिछले वर्ष के 4.14 मीट्रिक टन की तुलना में लगभग 14.7% बढ़कर 4.75 मीट्रिक टन हो गई।
	ईआरपी कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष के दौरान एसएपी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का पूर्ण गो-लाइव सीआईएल, एमसीएल, डब्ल्यूसीएल में चरण-I और ईसीएल, बीसीसीएल, सीसीएल, सीएमपीडीआई, एसईसीएल और एनसीएल चरण-II में शुरू किया गया था। दोनों चरण फिलहाल स्थिरीकरण के अंतिम चरण में हैं। परियोजना पर तेजी से काम करना सीआईएल परिकल्पित 51 महीने की समय-सीमा से 14.5 महीने पहले परियोजना को सफलतापूर्वक शुरू कर सकता है।
	पर्यावरण और ऊर्जा दक्षता • **पर्यावरण मंजूरी (ईसी) :** सीआईएल ने 21.94 एमटीवाई की वृद्धिशील क्षमता वाले 20 प्रस्तावों के लिए ईसी हासिल किया।
	• **वन मंजूरी (एफसी) :** सीआईएल ने 51.42 हेक्टेयर के 5 प्रस्तावों के लिए चरण-I एफसी और 1,081.24 हेक्टेयर के 5 प्रस्तावों के लिए अंतिम अनुमोदन (चरण-II एफसी) प्राप्त किया।
	• **पर्यावरण संबंधी पहल (ईएसजी) :** वर्ष के दौरान सीआईएल ने अपनी दूसरी ईएसजी रिपोर्ट प्रकाशित की है जो कि सीआईएल द्वारा अपने लक्ष्यों को एक स्थायी तरीके से प्राप्त करने के लिए किए जा रहे प्रयासों को दर्शाती है। किए गए सतत विकास गतिविधियां हैं :
	• **वृक्षारोपण :** सीआईएल की अनुषंगियों ने खनन पट्टा क्षेत्र के अंदर और बाहर 1,468 हेक्टेयर में वृक्षारोपण किया है।
	• **खान के पानी का उपयोग :** 2,458 एलकेएल खान के पानी का इस्तेमाल खुद के इस्तेमाल (औद्योगिक और घरेलू) और 2,249 एलकेएल सामुदायिक आपूर्ति के लिए किया गया, जिसमें 727 गांवों के 10.68 लाख लोग लाभान्वित हुए।
	2021-22 में सीआईएल का सौर ऊर्जा कार्यक्रम-सीआईएल ने तीन सहायक कंपनियों में कुल 240 मेगावाट (एसी) क्षमता वाली ग्राउंड माउंटेड सौर परियोजनाओं और लगभग 1192 करोड़ रुपये (एमसीएल-50 मेगावाट, एनसीएल-50 मेगावाट, एसईसीएल-40 मेगावाट और सीआईएल-100 मेगावाट (गुजरात में) के कुल पुरस्कार मूल्य के साथ ईपीसी अनुबंध प्रदान किया है। विभिन्न सहायक कंपनियों में 3.6 मेगावाट की कुल अतिरिक्त रूफटॉप सौर क्षमता चालू की गई है। ये परियोजनाएं (ग्राउंड माउंटेड और रूफटॉप दोनों) प्रति वर्ष लगभग 529 मिलियन यूनिट सौर ऊर्जा का उत्पादन करेंगी और प्रति वर्ष लगभग 4,33,780 टन CO_2 के कम करेंगी।
	• **ऊर्जा दक्षता उपाय :** सीआईएल में विभिन्न ऊर्जा दक्षता उपाय किए जा रहे हैं। सीआईएल ने स्ट्रीट लाइटों में 95,700 एलईडी लाइट, 803 ऊर्जा कुशल एसी, 11,684 सुपर पंखे, 194 ऊर्जा कुशल वॉटर हीटर, 33 ऊर्जा कुशल मोटर और 910 ऑटो टाइमर लगाए हैं। इन कदमों से प्रति वर्ष 312.39 लाख kWh विद्युत की बचत और CO_2 पदचिह्न को 25610 टन/वर्ष तक कम करने की उम्मीद है।

वित्तीय बर्ष	प्रमुख उपलब्धियां
वित्तीय बर्ष 2021-22 (ऑकड़े अनंतिम हैं)	**नई पहल** सीआईएल ने कंपनी को मौजूदा डीजल डंपरों में दोहरे ईंधन (डीजल-एलएनजी) संचालन शुरू करने की पहल की है। कार्बन उत्सर्जन में कमी पर प्रभाव सहित तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के लिए सीआईएल ने गेल और बीईएमएल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एक पायलट प्रोजेक्ट के लिए। दो मौजूदा डीजल संचालित बीईएमएल में एलएनजी किट को रेट्रोफिटिंग करके एमसीएल के लखनपुर ओसीपी में 100 टन डंपर को एलएनजी किट के साथ रेट्रोफिट किया गया।
	रेत पृथक्करण संयंत्र अपने विविधीकरण उपायों में से एक के रूप में, सीआईएल ने प्रसंस्करण और रेत निष्कर्षण के माध्यम से ओबी के लाभकारी उपयोग के लिए रेत पृथक्करण संयंत्र स्थापित करने की पहल की है। इससे रेत के व्यवसायिक और आंतरिक उपयोग में आसानी होती है। एक अन्य लाभ पर्यावरण संरक्षण है क्योंकि यह नदी से रेत निकालने को आसान बनाता है। वर्तमान में डब्ल्यूसीएल में दो रेत पृथक्करण संयंत्र प्रचालन में हैं। बिल्ड-ओन अवधारणा पर एक एकीकृत मॉडल बोली दस्तावेज तैयार किया गया है और अधिक रेत संयंत्रों की स्थापना के लिए सीआईएल की सहायक कंपनियों को परिचालित किया गया है।
	सीएसआर पहल और कोविड से निपटना • कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान, 'मिशन प्राण वायु' के तहत सीआईएल ने रुपये 46 करोड़ की लागत से 31 प्रेशर स्विंग सोखना (पीएसए) ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने की पहल की। 28 अस्पतालों में इनमें 24 सरकारी अस्पताल 4 कंपनी अस्पताल हैं। 35,000 लीटर प्रति मिनट की उत्पादन क्षमता के साथ ये संयंत्र निरंतर चिकित्सा ऑक्सीजन आपूर्ति के साथ 5,100 बिस्तरों का समर्थन कर सकते हैं। जबकि 25 संयंत्र पहले ही चालू हो चुके हैं, और बाकी पूरा होने के रास्ते पर हैं।
	• सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियां सीएसआर के तहत लगभग रु. 507 करोड़ (अनंतिम) का उपयोग करने में सक्षम हैं। वर्ष के दौरान स्वीकृत कुछ प्रमुख सीएसआर कार्यों में नागपुर में कैंसर अस्पताल के बुनियादी ढांचे का उन्नयन शामिल था।
	• अन्य सीएसआर पहलों में भोपाल, ग्वालियर और बेंगलुरु में 3 खेल छात्रावासों का निर्माण, कोलकाता में कैंसर के इलाज के लिए उच्च मूल्य के उपकरण उपलब्ध कराना, सुंदरगढ़ जिले (ओडिशा) के विभिन्न गांवों में 230 सामुदायिक केंद्रों का निर्माण और झारसुगुडा और भुवनेश्वर में वृक्षारोपण आदि शामिल हैं।
	• जैसे ही कोविड की दूसरी लहर चरम पर पहुंचने लगी, सीआईएल की सहायक कंपनियों ने कुल 3,764 बिस्तर उपलब्ध कराए हैं।
	• 50 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में भाग लिया गया, जिसमें 50 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के यात्रियों के बीच 71,621 भोजन के पैकेट के साथ पानी की बोतलें समान संख्या में वितरित की गईं। इसके अलावा 2,81,815 पके हुए भोजन के पैकेट और 1,36,168 पैकेट सूखे भोजन के राशन वितरण किया गया।
	• अभी तक सीआईएल की अनुषंगियों में 11,06,291 टीकाकरण खुराकें दी जा चुकी हैं और यह कार्यक्रम जारी है।

वित्तीय बर्ष	प्रमुख उपलब्धियां
वित्तीय बर्ष 2021-22 (ऑकड़े अनंतिम हैं)	**कर्मचारी शिक्षण और व्यावसायिक प्रशिक्षण**
	• बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों का प्रशिक्षण : प्रभावी योग्यता विकास के लिए, सीआईएल ने देश के प्रमुख प्रबंधन संस्थानों जैसे आईआईएम (कलकत्ता, इंदौर, लखनऊ) और एक्सएलआरआई (जमशेदपुर) के साथ बोर्ड स्तर से नीचे के लगभग 1800 अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
	• आईआईएम संबलपुर के माध्यम से 59 महिला अधिकारियों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कोविड-19 खतरे के बावजूद, 890 नए नियुक्त (प्रबंधन प्रशिक्षु) आईआईसीएम में ऑनलाइन इंडक्शन ट्रेनिंग से गुजरे हैं।
	• **गैर-कार्यपालकों का प्रशिक्षण** : 48,246 गैर-कार्यकारियों को सीआईएल और सहायक कंपनियों में प्रशिक्षित किया गया है। प्रशिक्षण में कार्यात्मक और व्यवहार संबंधी पहलू शामिल थे।
	• **संविदा कर्मियों का प्रशिक्षण : खान व्यावसायिक प्रशिक्षण नियमों की आवश्यकता के अनुसार** 33,206 ठेकेदार श्रमिकों को सीआईएल के व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
	• **प्रशिक्षुओं की नियुक्ति** : सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियां 2.5% की वैधानिक सीमा से आगे निकल गईं। 6,207 प्रशिक्षुओं को सीआईएल और अनुषंगियों में एक साल का ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण दिया गया था।
	सीएमपीडीआई का प्रदर्शन
	• 24 भूवैज्ञानिक रिपोर्टों के माध्यम से लगभग 315 वर्ग किमी के क्षेत्र को कवर करते हुए विस्तृत अन्वेषण के माध्यम से लगभग 8.5 बिलियन टन कोयला संसाधनों को प्रमाणित श्रेणी में जोड़े जाने की उम्मीद है। इसके अलावा, 6 भूवैज्ञानिक रिपोर्टों के माध्यम से लगभग 156 वर्ग किमी के क्षेत्र को कवर करते हुए प्रचार (क्षेत्रीय) अन्वेषण के माध्यम से लगभग 5.7 बिलियन टन नए कोयला संसाधनों (संकेत और अनुमानित श्रेणी) का अनुमान लगाया गया था। इसके अलावा, 2 भूवैज्ञानिक रिपोर्टों के माध्यम से लगभग 83 वर्ग किमी के क्षेत्र को कवर करने वाले 0.16 बिलियन टन नए लिग्नाइट संसाघनों (संकेत और अनुमानित श्रेणी) का अनुमान लगाया गया था।
	• सीएमपीडीआई से 7.50 लाख मीटर के एमओयू लक्ष्य के मुकाबले 7.94 लाख मीटर ड्रिलिंग करने की उम्मीद है, जिसमें 1.18 लाख मीटर प्रमोशनल एक्सप्लोरेशन शामिल है। इसके अलावा, 1.50 लाख के लक्ष्य के मुकाबले प्रचार (क्षेत्रीय) अन्वेषण के तहत कुल 1.69 लाख मीटर ड्रिलिंग (सीएमपीडीआई द्वारा 1.18 लाख मीटर सहित) की गई।
	• 2021-22 के दौरान लगभग 865 लाइन किमी 2डी-3डी भूकंपीय सर्वेक्षण किया गया, जबकि पिछले वर्ष की उपलब्धि 295.37 लाइन किमी 193% की वृद्धि के साथ थी।
	• एनएमईटी से पहली बार मिला काम लगभग 24 करोड़ रुपये की लागत वाली 6 परियोजनाओं (1 बॉक्साइट परियोजना सहित) को एनएमईटी द्वारा अनुमोदित किया गया था। 2 प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया है।
	• सीएमपीडीआई, केवल पीएसयू, क्यूसीआई एनएबीईटी द्वारा जीडब्ल्यूसीओं (भूजल सलाहकार संगठन) से मान्यता प्राप्त है।
	• प्रति वर्ष लगभग 69 मिलियन टन क्षमता वृद्धि के साथ 30 परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई।
	• ड्राफ्ट ईएमपी/फॉर्म-I/IV/VI की 50 रिपोर्टें तैयार की गईं। 74.54 एमटीवाई का इंक्रीमेंटल ईसी प्राप्त/अनुशंसित।

Scan this QR code to visit Ministry of Coal's YouTube channel

Scan this QR code to visit Coal India's YouTube channel

Printed at : Saraswaty Press Limited